▶▶ कृषि ▶▶ विश्लेषण ▶▶ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

आषाढ़–श्रावण 2077, जुलाई 2020

आत्मनिर्भरता संग चीन को सबक

VOICE OF SELF RELIANT INDIA

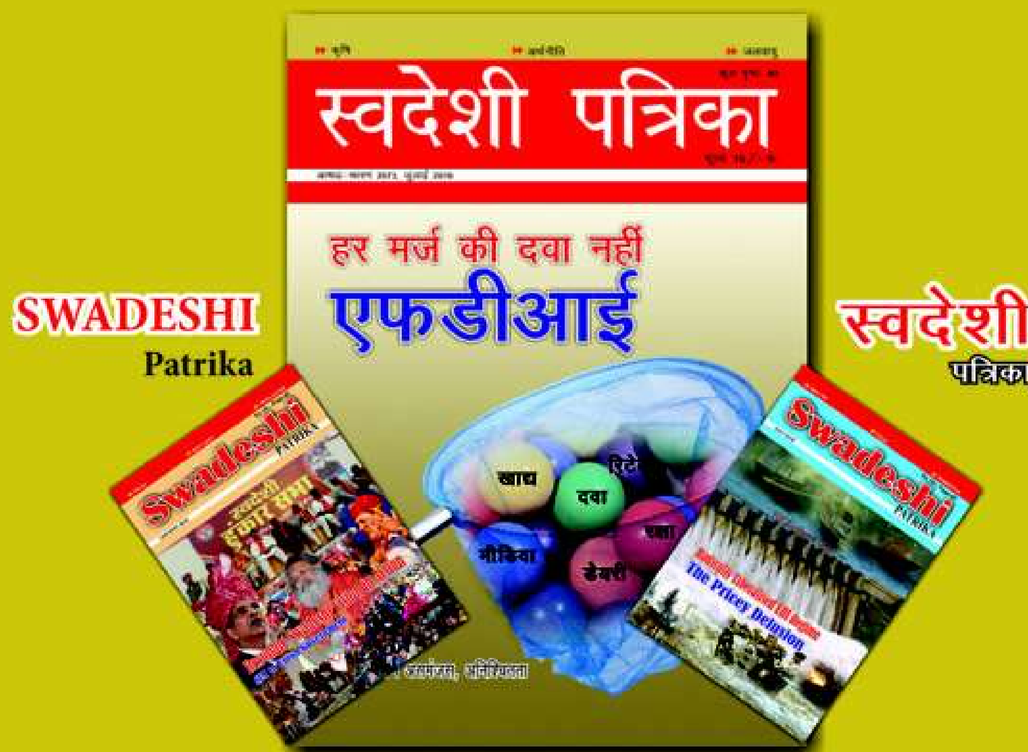

वार्षिक सदस्यता **(Annual Subscription) :** **150/-**

आजीवन सदस्यता **(Life Membership) :** **1500/-**

For subscription please send payment by A/c payee Cheque/Demand Draft/Money Order in favour of 'Swadeshi Patrika' at New Delhi, or Deposit the subscription amount in

Bank of India, *A/c No.* **602510110002740,**
IFSC: BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

Kindly write your full name and address in capital letters.
If you do not receive any issue of Swadeshi Patrika, kindly e-mail us immediately or contact **Sh. Suraj Bhardwaj (9899225926)**

पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

वर्ष–28, अंक–7

आषाढ़–श्रावण 2077 जुलाई 2020

संपादक

अजेय भारती

सह–संपादक

अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा / उन्होंने कहा **4**

समाचार परिक्रमा **34-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

आवरण कथा – पृष्ठ–6

आत्मनिर्भरता संग चीन को सबक

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 आवरण कथा
अपने ही ऋणजाल के षड़यंत्र से ढ़हती चीनी अर्थव्यवस्था
.... प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा

11 आवरण कथा
तिब्बत के साथ खुलकर खड़ा होना होगा भारत को
.... अनिल तिवारी

13 आवरण कथा
चीन–भारत संघर्ष के तात्कालिक कारण
.... दुलीचन्द कालीरमन

15 आवरण कथा
चीन से युद्ध के अलावा, आर्थिक मोर्चे पर भी नया फ्रंट जरूरी
.... विक्रम उपाध्याय

17 अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत
.... स्वदेशी संवाद

19 जैविक भारत
आत्मनिर्भर बीज स्वराज और अन्न स्वराज की ओर भारत
.... डॉ. वंदना शिवा

22 आत्मनिर्भर-भारत
किसान ही बनायेगा भारत को आत्मनिर्भर
.... सूर्यप्रकाश अग्रवाल

24 दृष्टिकोण
मुक्त व्यापार नहीं उबारेगा हमें
.... डॉ. भरत झुनझुनवाला

26 कृषि
संकट में जीवनरेखा बनी कृषि
.... देविन्दर शर्मा

28 जल प्रबंधन
देश के कई हिस्सों में बाढ़ की विभीषिका
.... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

31 मुद्दा
दीर्घकालीन नीति से ही बदलेगा बुंदेखण्ड
.... जयप्रकाश मिश्र

33 रिपोर्ट
सोशल मीडिया पर छाए रहे स्वदेशी योद्धा

पाठकनामा

भारत चीन के मध्य बढ़ते व्यापारिक प्रतिरोध

मैं लोकप्रिय स्वदेशी पत्रिका के माध्यम से जनता का ध्यान भारत चीन के मध्य बढ़ते व्यापारिक गतिरोध के संबंध में आकर्षित करना चाहती हूं। बीते दिनों सरकार ने टिकटाक समेत 59 चीनी मोबाइल एप्स को बैन करने का फैसला आधिकारिक तौर पर देश की संप्रभुता और सुरक्षा संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया है। दुनिया जानती है कि यह चीन के खिलाफ की गई ठोस जवाबी कार्रवाई है। चार हफ्ते पहले सीमा पर हुई हिंसक झड़प में हमने अपने 20 जवानों को गवां दिया। उनकी शहादत के बाद से ही भारत सरकार चीन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने का दबाव महसूस कर रही थी। सैन्य कार्रवाई जितनी टाली जा सके उतना बेहतर है। ऐसे में मोबाइल एप्स को प्रतिबंधित करके देश में लोगों केगुस्से को शांत करने की कोशिश की गई है, वहीं चीन को भी एक करारा जवाब दिया है कि दोनों देशों के रिश्ते बिगाड़ना उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। चीन के उत्पादों के बहिष्कार का भी सरकार चरणबद्ध तरीके से कदम उठा रही है, जिससे चीन को कारोबारी मोर्चे पर भी घेरा जा सके।

इस क्रम में कोयले की कमर्शियल माइनिंग के साथ तेल और गैस ब्लॉक के आवंटन में चीन की कंपनियों को दूर रखा जा सकता है। चीनी एप्स को बैन करने के बाद अब सरकार चीन से आयातित माल पर भी सख्ती बरतने जा रही है। चाइनीज माल की फिजिकल जांच होगी। क्वालिटी और अन्य पैमाने पर उसे परखा जाएगा जो इन पैमानों पर खरा नहीं उतरेगा उसे वापस भेज दिया जाएगा। चीन ने भारत के इस फैसले की आलोचना की और कहा भारत का यह कदम दोनों देशों के लिए ठीक नहीं है। भारत ने अपने नियमों को सख्त करते हुए एक और फैसला लिया कि वह चीन और पाकिस्तान से बिजली उपकरण तब तक नहीं मांगेगा जब तक मांगना बहुत जरूरी ना हो। उपकरण आने पर तब लैब में जांच करानी होगी ताकि पता चल सके कि उससे कोई जासूसी तो नहीं हो रही। पूरे देश में चीन के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। ऐसे में जबकि भारत की जनता चीनी सामान के खिलाफ सड़कों पर है, सरकार को भी और अधिक कठा रूख अपनाना चाहिए।

वैदेही, *रोहिणी (दिल्ली)*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है, यह विकास का युग है ... जब भी हमने विस्तारवादी प्रवृत्तियों को देखा है, इनसे विश्व शांति के लिए खतरा पैदा हो गया है।

नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री, भारत)

अब आप केवल दो 'सी' सुन सकते हैं, एक- सी फोर कोरोना, दो- सी फोर चीन। हम समस्याओं को बातचीत के जरिये हल करने में यकीन रखते हैं, लेकिन अगर कोई भारत पर बुरी नजर डालता है तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे।

रविशंकर प्रसाद (संचार मंत्री, भारत)

देश के स्वदेशी उद्योगों का कायाकल्प करके आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है, जिसमें लघु उद्योग, लघु व्यवसाय, कारीगर, ग्रामीण उद्योग और अन्य गैर-कानूनी गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य रोजगार पर प्रोत्साहन के साथ समावेशी विकास करना है।

डॉ. अश्वनी महाजन (राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच)

चीनी निवेश के विकल्प

सोशल मीडिया एप्स, ई–कॉमर्स एप्स और अन्य प्रकार की एप्स के माध्यम से चीन लाभ तो कमा ही रहा है, साथ ही साथ हमारी जनता की बहुमूल्य जानकारियों को भी इकट्ठा कर चीन में भेजकर हमारे लिए सुरक्षा संकट उपस्थित करता है। इन सब करतूतों के विरोध में भारत सरकार ने भी अपना रुख सख्त कर दिया है। हाल ही में 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध और चीनी कंपनियों के ठेके रद्द करने का काम भारत सरकार ने किया है। इनके आयातों को रोकने के लिए आयात शुल्क बढ़ाने और अन्य गैर टैरिफ उपाय अपनाने की तैयारी की जा रही है। पिछले कुछ समय से चीनी कंपनियां और निवेशक, जिन्हें चीनी सरकार से अलग कर नहीं देखा जा सकता, भारी मात्रा में भारतीय स्टार्टअप और अन्य व्यवसायों में निवेश कर रहे हैं। यूं तो सीधे तौर पर भारत में चीन का निवेश मात्र 8 अरब डालर ही है, लेकिन जानकार मानते हैं कि चीन का वास्तविक निवेश इससे कहीं ज्यादा है क्योंकि चीनी कंपनियों, निवेशकों और सरकार ने छद्म रूप से अन्य देशों के माध्यम से भी भारत में निवेश किया है।

कुछ लोगों का यह कहना है कि क्योंकि चीन से निवेश आ रहा है, हमें इसे रोकना नहीं चाहिए क्योंकि इससे हमारे स्टार्टअप का वित्तीय पोषण बंद हो सकता है और देश में व्यवसायों और रोजगार पर असर पड़ सकता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि चीन से सस्ते आयात आने देना चाहिए क्योंकि इससे उत्पादकों की लागत कम होती है और वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे स्टार्टअप ही हमारे भविष्य के उद्योग और व्यवसाय हैं यदि चीनी निवेश के कारण उनका स्वामित्व और प्रबंधन चीनी हाथों में चला जाता है तो उससे कुछ भी भारतीय नहीं रहेगा। उनके व्यवसायिक निर्णय ही नहीं बहुमूल्य बाजार और डाटा भी चीनी हाथों में चला जाएगा। पेटीएम का उदाहरण हमारे सामने है। आज डिजिटल भुगतान में सबसे अधिक बाजार की हिस्सेदारी के साथ पेटीएम चीन के अलीबाबा के हाथों में है। वो अब बैंकिंग में भी पैर पसार रहा है। हाल ही में अलीबाबा ने पेटीएम के माध्यम से मृत प्रायः बीमा कंपनी रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को खरीदकर सीधे बीमा व्यवसाय में प्रवेश करने का प्रयास किया है। निष्कर्ष यह है कि चीनी निवेश को केवल निवेश के रूप में नहीं, बल्कि अपने व्यवसायों को चीनी हाथों में सौंपने के रूप में देखा जाना चाहिए। दूसरे आज चीन के बहिष्कार के चलते भारतीय उद्यमों, एप्स, भुगतान कंपनियों, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का व्यवसाय आगे बढ़ रहा है। ऐसे में यदि इन कंपनियों में चीनी निवेश रोका नहीं गया, तो यह कंपनियां भी देर सबेर चीनी हाथों में चली जाएँगी और देश हाथ मलता रह जाएगा। जरूरी है भारतीय निवेशकों द्वारा निवेश से उद्यमों को चीनी हाथों में जाने से रोका जाए। इसके लिए जरूरी है कि हमारे भारतीय निवेशक भारतीय स्टार्टअप में निवेश करें। पिछले काफी पिछले काफी समय से भारतीय निवेशक उद्यम पूंजी (वेंचर कैपिटल) के माध्यम से भारतीय स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं।

इस उद्यम पूंजी यानि वेंचर कैपिटल में भारत के बड़े औद्योगिक घरानों, बड़े कारपोरेट और धनवान व्यक्तियों (हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स) का पैसा लगा है। सर्वविदित ही है कि स्टार्टअप का अभिप्राय है एक आइडिया या एक खोज, जिसके बलबूते हमारे युवा अपने कौशल के माध्यम से अपना उद्यम खड़ा करते हैं। ये उद्यम अधिकांशतरू ई–कॉमर्स, सोशल मीडिया एप्स, उपभोक्ता सेवाओं, औद्योगिक उत्पादन सेवाओं, कृषि से संबंधित व्यवसाय आदि में कार्य कर रहे हैं। चूँकि इन स्टार्टअप में अत्यधिक जोखिम होता है, इसलिए बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान उन्हें ऋण देने में कतराते हैं। लेकिन वेंचर कैपिटलिस्ट इन्हें आसानी से अंश पूंजी प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि कुछ स्टार्टअप के असफल होने पर भी सफल उद्यमियों से होने वाले लाभ उनकी हानि की भरपूर पूर्ति कर देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट भारतीय भी हैं और विदेशी भी। विदेशियों में चीनी, अमेरिकी यूरोपीय और अन्य देशों के फंड शामिल हैं। ऐसा देखने में आ रहा है कि भारत के ई–कॉमर्स और डिजिटल भुगतान में संबंधित स्टार्टअप कंपनियों में फंडों का निवेश बहुत अधिक बढ़ चुका है। चिंता की बात यह है कि इन ई–कॉमर्स, सोशल मीडिया और भुगतान कंपनियों के स्वामित्व के माध्यम से चीन हमारे यहां से बहुत सा बहुमूल्य डाटा अपने देश में ले जा रहा है, जो हमारे व्यवसाय और आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा हमारे सामाजिक और ताने–बाने और धार्मिक सद्भाव के लिए भारी खतरा है। इसके लिए जरूरी है कि न केवल आगे आने वाले चीनी निवेश को रोका जाए बल्कि यथासंभव पूर्व में जिन कंपनियों में चीनी निवेश हो चुका है उसे वापस करने हेतु उपाय खोजे जाएं।

सर्वविदित है कि भारत में पूंजी की लागत अधिक है, इसलिए कंपनियां चीन समेत अन्य देशों से कम ब्याज पर ऋण लेती रही हैं। भारतीय वेंचर कैपिटलिस्टों के लिए भी वित्त की लागत बहुत अधिक होती है। अधिकांश वेंचर कैपिटलिस्ट फंडों में निवेश करने वाले लोग अपनी आमदनी पर पूरा टैक्स देने के बाद स्टार्टअप में निवेश करने के लिए धन उपलब्ध करवाते हैं।

आज बदली हुई परिस्थितियों में जहां चीन से निवेश आना अनापेक्षित है, कम से कम कर देयता में समता का सिद्धांत लागू कर हम भारतीय निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं। चीनी निवेश को रोकने और पूर्व में किए निवेश को वापस करने से देश को कई लाभ होंगे। हमारे युवाओं के स्टार्टअप देश के स्वामित्व में रहेंगे और युवाओं के आईडिया और बौद्धिक संपदा का पलायन नहीं होगा। चीन एक शत्रु देश होने के कारण उसकी पूंजी को अवसर नहीं मिलने से उसकी आर्थिक शक्ति भी क्षीण होगी।

आत्मनिर्भरता संग चीन को सबक

आज दुनिया भर के लगभग सभी देश चीन से आए वायरस से जूझ रहे हैं, जिससे अभी तक 91 लाख लोगों को संक्रमण हो चुका है और 4.72 लाख लोग मृत्यु को भी प्राप्त कर चुके हैं। यदि इसे चीन का षड्यंत्र न भी माना जाए तो भी यह तो सर्वविदित ही है कि चीन ने इसकी भयावहता को दुनिया से छुपाया और अपनी वैश्विक विमान सेवाओं को जारी रखते हुए जानबूझकर संक्रमित लोगों को दुनिया भर में पहुंचा दिया, जिससे यह संक्रमण दुनिया भर में फैल गया। इस संक्रमण ने दुनियाभर को अपनी चपेट में ले लिया। चीन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार से दुनिया भर में न केवल लोग स्वास्थ्य संकट से जूझ रहे हैं बल्कि एक भयंकर आर्थिक संकट का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 3 माह से ज्यादा समय से आर्थिक गतिविधियां लगभग पूरी तरह से ठप्प पड़ी हैं। पिछले लगभग 20 वर्षों में जब से चीन डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना है, उसने अपने सस्ते सामानों के द्वारा दुनिया भर के बाजारों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देश सभी चीन के माल पर आश्रित हैं, क्योंकि उनके उद्योग चीन से सस्ते माल से प्रतिस्पर्धा न कर पाने के कारण नष्ट हो चुके हैं। ऐसे में चीन अमेरिका के मुकाबले दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। खरबों डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के बलबूते उसने 67 देशों को मिलाकर एक बेल्ट रोड परियोजना की भी शुरुआत कर दी है, ताकि एक ओर दुनिया के बड़े हिस्से के इंफ्रास्ट्रक्चर पर वह कब्जा कर सके और साथ ही साथ अधिकांश देशों को अपने जाल में फंसा कर उनके उन इलाकों को कब्जा कर सके जो चीन की सामरिक शक्ति को बढ़ाने में सहयोगी हों। श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पर कब्जा चीन की उसी कुटिल नीति का एक उदाहरण है।

चीन ने इस बीच अपनी आर्थिक शक्ति के साथ अपनी सामरिक शक्ति को भी विस्तार दिया है। चीन का अभी तक का इतिहास विस्तार वाद का ही रहा है।1962 में हमारी हजारों किलोमीटर भूमि पर अधिकार जमा लेना उसी नीति का हिस्सा था। वर्ष 2001 के बाद से उसने अपनी विस्तार वादी नीति को और तेजी से बढ़ाना शुरू किया है। हालांकि अमेरिका

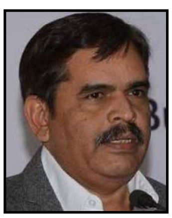

सस्ते चीनी सामानों के नाम पर हम अपनी अर्थव्यवस्था को गर्त में नहीं डाल सकते। करोना के बाद आज एक चुनौती आई है उसे अवसर में बदलने का नाम ही भारत का आत्मनिर्भरता अभियान है।
– डॉ. अश्वनी महाजन

ने पहले से ही चीन की धोखेबाजीपूर्ण व्यापार नीति के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ रखा है और उसकी हुआवे जैसी कंपनियों को भी अपने टेलीकॉम क्षेत्र से बाहर कर रहा है। कोरोना संकट के बाद तो लगभग हर देश चीन से किनारा कर रहा है। भारत समेत कई अन्य यूरोपीय देशों ने भी चीन की घटिया और नकली टेस्ट किट्स की खेपों को वापस भेज कर अपनी नाराजगी स्पष्ट कर दी है। जहां अमेरिका का चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध बदस्तूर जारी है, वहीं यूरोपीय समुदाय के देशों ने भी चीन पर विशेष आयात शुल्क लगाने का फैसला किया है। यह इसलिए किया गया है कि यूरोपीय समुदाय के देश यह मानते हैं कि चीन की सरकार अपने निर्यातों पर प्रोत्साहन राशि देकर उनको सस्ता कर यूरोप में भेजती है, जिसके कारण उनके उद्योगों को नुकसान हो रहा है। ऐसा लगता है कि चीन की बेल्ट रोड परियोजना भी खटाई में पड़ने जा रही है। पहले 67 देश उसमें भागीदार बन गए थे, लेकिन उनमें से कई देश तो पहले ही चीन के विस्तारवादी मंसूबों को समझकर उससे कन्नी काटने लगे थे। गौरतलब है कि मलेशिया ने पहले से ही अपने परियोजना को काफी छोटा कर दिया है। श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह को हथिया लेने के बाद श्रीलंका की जनता और सरकार चीन से अत्यधिक नाराज है। कई मुल्कों पर कर्जे के बोझ को बढ़ा देने के कारण भी वहाँ के लोग और सरकारें उससे नाराज हैं और उस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित नहीं। मालदीव, मंगोलिया, मोंटेगरो, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस समेत कई देश चीन के कर्ज जाल में फंस चुके हैं। इटली सरीखे यूरोपीय देश भी जो अमरीका के विरोध के बावजूद, पहले बेल्ट रोड योजना में शरीक हो गए थे, चीन से आने वाले कामगारों से संपर्क के कारण जो कोरोना महामारी की चपेट में आ गए, अब चीन के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने पर पुनर्विचार करने लगे हैं। अफ्रीकी देश, लेटिन अमेरिकी देश और ऑस्ट्रेलिया, सभी अब चीन से खफा हैं। ऑस्ट्रेलिया के भारत के साथ बढ़ते रिश्तों को लेकर भी चीन आशंकित हुआ है। यानी कहा जा सकता है कि भारत समेत पूरी दुनिया के देश चीन के माल का बहिष्कार कर रहे हैं। वहां की सरकारें चीन की कंपनियों से रिश्ते तोड़ रही हैं और चीन के माल को रोकने हेतु टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं खड़ी कर रही हैं और चीन के विस्तारवादी रवैये को देखते हुए चीन को सामरिक खतरे के रूप में देख रही हैं। ऐसी परिस्थिति को हम चीन का 'वैश्विक बहिष्कार' भी कह सकते हैं।

बहिष्कार की सफलता पर सवाल

चीन दुनिया भर में जनता के गुस्से, बहिष्कार और वहां की सरकारों के चीन के प्रति बढ़ते विरोध के चलते भारी चिंता में है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के हालिया लेख इसकी तश्दीक कर रहे हैं। भारत में अभी भी कई लोग हैं जो यह मानते हैं कि चीन का बहिष्कार फलीभूत नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी चीन पर अत्यधिक निर्भरता है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा उद्योगों के कच्चे माल (एपीआई), स्वास्थ्य उपकरण, केमिकल्स, धातुओं, खिलौनों, उद्योगों के लिए कलपुर्जों और कच्चे माल समेत हमारे देश की निर्भरता चीन पर इतनी अधिक है कि चीन का बहिष्कार संभव नहीं, और चीन के आयात पर रोक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह हो सकती है। उनका यह भी कहना है कि चीन के माल का पूर्ण बहिष्कार कर भी दिया जाए तो भी उस से चीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसके कुल निर्यात 2498 अरब डॉलर के मुकाबले भारत को उसके निर्यात मात्र 68.2 अरब डॉलर के ही हैं यानी मात्र 2.7 प्रतिशत।

हमें समझना होगा कि हमारे देश से चीन को कुल 50 अरब डॉलर का व्यापार अतिरेक प्राप्त होता है जो उसके कुल व्यापार अतिरेक (430 अरब डालर) का 11.6ः है। साथ ही नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका का चीन से व्यापार घाटा 360 अरब डॉलर का है जो चीन के व्यापार अतिरेक का 83ः से ज्यादा है। यदि भारत और अमेरिका दोनों मिलकर चीन के माल को अपने देशों से बाहर कर दें, तो चीन का सारा व्यापार अतिरेक समाप्त हो जाएगा। जहां तक भारत की चीन के आयात पर निर्भरता का प्रश्न है भारत की क्षमता को कम आंकना सही नहीं है। आज से 15 साल पहले तक दवाओं का कच्चा माल (एपीआई) का 90 भारत में ही बनाया जाता था, लेकिन चीन द्वारा डंपिंग के कारण हमारी एपीआई इंडस्ट्री प्रभावित हुई। उसे पुनः स्थापित करने हेतु सरकार ने 3000 करोड रुपए के पैकेज की घोषणा पहले से ही कर दी है। चीन से आने वाले कई उत्पाद जीरो टेक्नोलॉजी के हैं, जिनका उत्पादन भारत में तुरंत शुरू किया जा सकता है। हाल ही में मात्र 2 महीनों में भारत पीपीई किट्स, टेस्टिंग किट्स समेत कई मामलों में आत्मनिर्भर हो चुका है और अभी तक 50,000 से ज्यादा वेंटिलेटर भी भारत में तैयार हो चुके हैं, भारत की प्रतिभा और क्षमता पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। चीन से आने वाले उत्पादों की कीमत के आधार पर ही हम उसके आयतों को अनुमति दें, यह सही नहीं होगा। उसके आयातों के कारण देश में उद्योगों के पतन, बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी पर भी विचार करना होगा। सस्ते के नाम पर हम अपनी अर्थव्यवस्था को गर्त में नहीं डाल सकते। करोना के बाद आज एक चुनौती आई है उसे अवसर में बदलने का नाम ही भारत का आत्मनिर्भरता अभियान है। ❑❑

अपने ही ऋणजाल के षड़यंत्र से ढ़हती चीनी अथर्व्यवस्था

विकासशील देशों को ऋण के प्रलोभन में अपनी "बेल्ट एण्ड रोड़" परियोजना में सम्मिलित कर छदम शर्तों पर दिये ऋण के बदले में उनकी भूमि व संसाधनों को हस्तगत कर, आर्थिक उपनिवेश बनाने के षड़यंत्र में लिप्त चीन अब कोरोना संकट के चलते स्वयं ही दिवालियापन की ओर बढ़ रहा है। चीनी वायरस से फैली महामारी के कारण चीन की राजनयिक प्रतिष्ठा, अथर्व्यवस्था और उसकी अत्यन्त महत्वाकांक्षी 'बेल्ट एण्ड रोड' परियोजना गंभीर संकट में पड़ी दिखाई दे रहीं हैं।

ऋणजाल के कुचक्र पर आधारित बेल्ट एण्ड रोड़ परियोजना

अपने विशाल विदेशी मुद्रा भण्डार और वृहद निमार्ण कंपनियों के सहारे विश्व भर में आधारभूत संरचनाओं के लिए ऊँची ब्याज दर, अपारदर्शी शर्तों पर परियोजनाओं के निमार्ण के बाद उन देशों की संपत्तियों को अधिग्रहीत कर आर्थिक उपनिवेश की स्थापना में लगे चीन से धीरे–धीरे अब अधिकांश देश अलग होते जा रहे हैं। ऋण के बदले में उसकी बेल्ट एण्ड रोड़ परियोजना में सम्मिलित लगभग 78 देशों में से कई देश अब कोविड महामारी के कारण उस ऋण की अदायगी के योग्य ही नहीं रह गये हैं। इससे चीन के अरबों डॉलर के ये ऋण डूबने के कगार पर हैं। बेल्ट एण्ड रोड़ परियोजना, जिसे नया सिल्क रूट कहा जा रहा है, एक ऐसी "विशाल व्यापार, निवेश और आधारभूत–संरचना विकास की परियोजना है, जिसका उद्देश्य भौगोलिक, व्यापारिक एवं वित्तीय रूप से एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दुनिया के अनेकों देशों को जोड़ना बताया जाता रहा है। इसमें सड़क, रेल मार्ग, सामुद्रिक मार्ग तीनों ही प्रकार के परिवहन की आधारभूत संरचनाओं का निमार्ण सम्मिलित है। परियोजना में सम्मिलित देशों के साथ पारदर्शिता रहित अनुबन्धों, अत्यन्त ऊंची व अव्यवहारिक ब्याज दरों, भ्रष्ट शासकों को आर्थिक प्रलोभन और ऋणग्राही देशों को बिना जानकारी दिये सीधे चीनी कम्पनियों को निमार्ण कार्यों का ऊँची दरों पर किये भुगतान आदि के कारण अब वे देश उस ऋण को चुकाने की स्थिति में ही नहीं हैं। *छलपूवर्क अपनी ही कम्पनियों को ऊंची लागत पर सीधे–सीधे छदम रीति से भुगतान करते रहने से उन सरकारों को, पूरी निमार्ण अवधि के दौरान भी यह पता नहीं होता था कि इस प्रकार के छदम भुगतानों से चीन ने कितना ऋण उनके नाम चढ़ा दिया है। फिर उस छदम ऋण को चुकाने में विफल रहने वाले देशों की उस सम्पूर्ण परियोजना व अन्य समपाश्विर्क सम्पित्तयों को चीनी कम्पनियाँ हस्तगत कर लेती रहीं हैं।* श्रीलंका के हंबनटोटा व अफ्रीका में जीबूती का बन्दरगाह, केन्या का मोम्बासा बन्दरगाह आदि ऐसे कई उदाहरण हैं। ऋण के बदले उन सम्पित्तयों व उस देश के अन्य संसाधनों को 99 वर्ष के लिए की लीज पर बलपूवर्क हथिया कर वहाँ अपने सैन्य अड्डे तक बना लिए हैं। चीन के इस ऋणजाल के चक्रव्यूह को समझकर अब अधिकांश ऋणग्राही देशों ने उन ऋणों की अदायगी में असमथर्ता बतानी आरम्भ कर उस जाल को ध्वस्त करना आरम्भ कर दिया है।

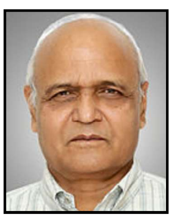

चीन की सामरिक क्षमताओं का आधार आर्थिक है। वर्ष 2018 में भारत के आयात ही 90 अरब डालर (लगभग रूपये 7 लाख करोड़) के थे। अब आत्मनिभर्र भारत अभियान के फलस्वरूप घटकर अत्यंत न्यून रह जायेंगे। जापान, अमेरिका व यूरोप सहित अधिकांश देशों द्वारा आर्थिक बहिष्कार चीन को पराभव की ओर ले जायेगा।

– प्रो भगवती प्रकाश शर्मा

भुगतान विलम्बन और ऋणों के डूबने का संशय

पाकिस्तान सहित अधिकांश ऋणग्राही देशों ने अब कोविड–19 महामारी के बाद चीन से लिये ऋणों के पुनर्भुगतान के लिये 10–10 वर्ष के अतिरिक्त समय की मांग कर दी है। चीन के पास इन सभी देशों की इस मांग को स्वीकारने के अतिरिक्त कोई विकल्प भी नहीं है। अपने ही वुहान वायरस से वैश्विक अथर्व्यवस्था में आये गतिरोध के बाद अब चीन द्वारा कई देशों को दिये ऋण वापस कदाचित ही मिल पाएंगे। कई देश चीन के इस ऋणजाल के कुचक्रों की कार्य प्रणाली को समझ चुके हैं। *पिछले सप्ताह में ही केन्या में एक जनहित याचिका पर निर्णय करते हुये न्यायालय ने चीन द्वारा ऐसे ऋणजाल से बनाये एक स्टेण्डर्ड गेज रेल मार्ग के 3.2 अरब डॉलर (25,000 करोड़ रूपये तुल्य राशि) के अनुबन्ध को अवैध घोषित कर दिया है। अब चीन के ऋण से बनी परियोजनाओं पर ऐसे न्यायिक निर्णयों की सभी देशों में बाढ़ आ सकती है।* पिछले वर्ष ही दो अफ्रीकी देशों– सियरा लियोन और तंजानिया ने भी "बेल्ट एण्ड रोड़ परियोजना" से स्वयं को अलग कर लिया था। दो वर्ष पूर्व 2018 में म्यांमार ने भी चीन के सहयोग से बनने वाले क्यायूकफ्यू बन्दरगाह प्रोजेक्ट को अत्यन्त छोटा कर दिया था। इस बन्दरगाह को भी चीन के बेल्ट एण्ड रोड़ इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के अधीन ही बनाया जाना था। मलेशिया में भी ईस्ट कोस्ट रेल लिंक (ईसीआरएल) प्रोजेक्ट की लागत भी शुरू से दो तिहाई घटा दी गई थी। *कम्बोडिया में तो चीन का भारी जनविरोध भी आरम्भ हो गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के सबसे बड़े साझेदार देश की जनता को भय है कि कहीं कम्बोडिया चीन के अधीन न हो जाए। काउंसिल फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ़ कंबोडिया के मुताबिक, चीन ने 2016 में 3.6 अरब डॉलर का निवेश किया था, जो एक साल बाद दोगुना बढ़कर 6.3 अरब डालर हो गया। कम्बोडियाई सरकार ने कोह कोंग प्रांत को चीन की एक कम्पनी को 99 साल की लीज पर दिया, जो देश के कुल कोस्टलाइन का 20 प्रतिशत है।*

इस प्रकार "बेल्ट एण्ड रोड़ परियोजना" के साझेदार देशों में बढ़ती जागृति, चीनी ऋणजाल के कुचक्र और वुहान वायरस के कारण उनमें आ रही आर्थिक गिरावट आदि से उसकी यह बेल्ट एण्ड रोड़ परियोजना भी ढह जाने की सम्भावनाएं बढ़ने लगीं है। इसी कारण से परियोजना के सदस्य कई देश चीन को ऋण को चुकाने में देरी के लिए बाध्य कर रहे है। पाकिस्तान तक ऋणों के पुनर्भुगतान में दस वर्ष की देरी चाहता है और कई अफ्रीकी देश भी कर्ज–माफी की मांग कर रहे है। चीन ऐसे समय में, जब उसकी राजनयिक प्रतिष्ठा अपने न्यूनतम स्तर पर है, इन देशों की मांगों को ख़ारिज नहीं कर सकता है। आज उसकी प्रतिष्ठा का स्तर थियानमान चौक की घटनाओं या तिब्बत को हस्तगत करने के समय से भी नीचे गिर चुकी है। इसलिए, बीजिंग ने लगभग 77 देशों के लिए ऋण पुनर्भुगतान स्थगित कर दिया है। इनमें से 40 तो अफ्रीकी देश हैं। वर्ष 2019 में, बीजिंग ने लगभग अमेरिका सहित विश्व के 150 देशों को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दे रखा होने का आकलन है, जिसका एक भाग अब डूबने के कगार पर है या विलम्ब से प्राप्त होगा।

वर्ष 2013 में ही चीन ने अपना निवेश व्यापार बढ़ाने के लिए 3.87 ट्रिलियन डॉलर और 2951 अंगभूत परियोजनाओं से युक्त यह अति महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अधीन 'बेल्ट एण्ड रोड़ इनिशिएटिव' नाम से प्रस्तावित किया था। इस परियोजना के अन्तगर्त ही विकास के नाम पर चीन ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण–पूर्व एशिया, मध्य एशिया और यूरोप में अरबों डॉलर की कई परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है। अन्य देश विकास के नाम पर ऋण लेते गए और चीन देता गया। अब लगभग 20 प्रतिशत बेल्ट एण्ड रोड़ परियोजनायें कोरोना महामारी से उपजे आर्थिक संकट के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हैं व 40 प्रतिशत परियोजनायें न्यूनाधिक सीमा में प्रभावित हुयी हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार इस परियोजना के लिए चीन ने विश्व के 150 देशों को 1. 5 ट्रिलियन डॉलर (115 लाख करोड़ रूपये तुल्य) ऋण दे रखा है, जबकि विश्व बैंक व मुद्राकोष द्वारा केवल 500 अरब डॉलर का ही ऋण दिया हुआ है। अमेरिका पर चीन के 1.04 ट्रिलियन डॉलर के ऋण सहित विश्व के सभी देशें में चीन की कुल बकाया उधारी लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर (375 लाख करोड़) की है। यदि वुहान वायरस की क्षतिपूर्ति के बदले सभी देश सामूहिक निणर्य लेकर इस ऋण को चुकता घोषित कर दें तो चीन का दिवालिया होना अवश्यम्भावी है, जिसके लिए विश्व का जनमानस तैयार करना कठिन, पर असम्भव नहीं है।

उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर चीनी परियोजना पर भारत की काट

पाक अधिकृत कश्मीर से निकलने वाला चीन–पाक आर्थिक गलियारा भी इसी बेल्ट एण्ड रोड़ परियोजना का अंग होने से भारत ने तो आरम्भ से ही चीन के बेल्ट एण्ड रोड़ फोरम में हिस्सा लेने से स्पष्ट मना कर दिया है। मुम्बई से चाबहार के रास्ते उत्तरी यूरोप तक 13 देशें की भागीदारी वाली "अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन कॉरिडोर" योजना इस चीनी परियोजना का बेहतर विकल्प ही नहीं उसका काट भी है। रेल, सड़क और समुद्री परिवहन वाले 7200

किलोमीटर लम्बे इस "अंतर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन कॉरिडोर" पर भारत, रूस और ईरान ने साल 2000 में सहमति बनाई थी। यह कॉरिडोर हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के जरिये कैस्पियन सागर से जोड़ेगा और फिर रूस से होते हुए उत्तरी यूरोप तक भारत की व्यापारिक पहुँच बनाएगा। इसके अन्तगर्त ईरान, अजरबैजान और रूस के रेल मार्ग भी भारत से जुड़ जाएंगे। इसी उत्तर दक्षिण कॉरिडोर योजना के अधीन ही भारत ईरान के चाबहार बन्दरगाह का विकास कर रहा है। चाबहार के रास्ते भारत कोरोना महामारी के चलते अफगानिस्तान को खाद्यान्न व दवाईयों की पूर्ति कर सका है। चीन के "बेल्ट एण्ड इनिशिएटिव" के काट के रूप में देखते हुये अमेरिका ने ईरान पर आरोपित आर्थिक प्रतिबन्ध से भी मुक्त रखा हुआ है। इसमें 13 देश भारत, ईरान, रूस, टर्की, अजरबेजान, कजाखस्तान, आर्मेनिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ओमान, यूक्रेन व सीरिया सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं और बुल्गारिया आब्जर्वर या पयर्वेक्षक की भूमिका में है। वतर्मान में मुंबई से मास्को या सेंटपीटरसबर्ग माल भेजने में 40–45 दिन का समय लगता है। अगर उसे इस उत्तर–दक्षिण कॉरिडोर के रूट से भेजेंगे तो यह 25 दिन में पहुंच जायेगा। इसमें समय के साथ–साथ व्यय भी 40 प्रतिशत से कम आयेगा, जिससे हमारा व्यापार बढ़ेगा। यह कॉरिडोर हमारे व्यापार के साथ–साथ सेंट्रल एशिया में हमारे रणनीतिक हितों के लिये भी महत्त्वपूर्ण है। भारत ने अफगानिस्तान में एक सड़क इसी श्रृंखला में बनाई है जिससे वहाँ की स्थिरता और शांति स्थापना में भी हम योगदान दे सकेंगे और यह कॉरिडोर सामरिक दृष्टि से भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगा।

"ब्लूडॉट नेटवर्क" भी चीनी "बेल्ट एण्ड रोड़" परियोजना का विकल्प

हाल ही में अमेरिका, जापान व आस्ट्रेलिया द्वारा प्रस्तावित ब्लू डॉट नेटवर्क भी चीन के बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव का बहुत अच्छा अमेरिकी काट है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के अवसर पर फरवरी 25 के संयुक्त वक्तव्य में भारत ने भी अपनी रुचि व्यक्त कर दी है। इसे नवंबर 2019 में थाईलैंड में ही इंडो–पैसिफिक बिजनेस फोरम में जापान, आस्ट्रेलिया व अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया था। भारत भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ चार देशों के संयुक्त रणनीतिक समूह 'क्वाड' का पहले से ही सदस्य है।

विश्व भर में उच्च गुणवत्ता वाली आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले, टिकाऊ और भरोसेमंद विकल्पों की पहुँच हो, इसलिए कई देश 'बेल्ट एण्ड रोड़' के स्थान पर ब्लू डॉट नेटवर्क के अधीन आधारभूत संरचनाओं के विकास को प्राथमिकता देंगे। भारत–अमेरिकी संयुक्त बयान के अनुसार, ब्लू डॉट नेटवर्क "एक बहुहितधारक पहल होगी जो वैश्विक आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए उच्च गुणवत्ता वाले विश्वसनीय मानकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी को एक साथ लाएगा"।

आज अमेरिकी बेस रेट (ब्याज दर) जो हमारी रेपो दर की तरह होती है, शून्य होने से चीन के 6.5–7 प्रतिशत ब्याज के स्थान पर इस योजना में वित्तीय लागत अत्यन्त कम होगी। ऋणजाल में फँसने वाली चीनी बेल्ट एण्ड रोड़ परियोजना के स्थान पर भारत का "अन्तर्राष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण गलियारा योजना" और ब्लू डॉट नेटवर्क जैसी न्याययुक्त व पारदर्शी योजनाएँ विश्व को बेहतर विकल्प देगी।

भारत की समयोचित दृढ़ता

भारत ने हाल ही में गलवान घाटी की घटनाओं के बाद आवश्यक दृढ़ता दिखाते हुये दूरसंचार, निमार्ण, रेल परियोजनाओं में और अन्य कई क्षेत्रों में चीनी कंपनियों की भागीदारी पर जो रोक लगायी है। उसका चीनी अथर्व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ेगा। अमेरिका द्वारा चीनी आयातों से लेकर, अमेरिकी शेयर बाजार में चीनी कंपनियों के सूचीयन तक पर जो प्रतिबन्ध लगाये है उसके कारण और यूरोपीय देश जो चीन पर कई प्रतिबंध लगा रहे है, उनके कारण चीन की निर्यात आधारित अथर्व्यवस्था का चरमराना स्वाभाविक है। *चीन 1849 से 1949 की अवधि को चीनी इतिहास का एक शमर्नाक काला अध्याय मानता है। वर्ष 1899 में तो उसे हॉगकॉग को भी 100 वर्ष के लिए इंग्लैण्ड को लीज पर देना पड़ा था। अब वुहान के वायरस के बाद और भारत से शत्रुतापूर्ण व्यवहार के बाद आने वाली गिरावट से चीनी इतिहास का 2020 से दूसरा शमर्नाक काला अध्याय आरम्भ होगा।* इसलिए अब भारत को भी 'वन चाइना' अथार्त एकल समेकित चीन के स्थान पर "त्रिराष्ट्र युक्त चीन" अथार्त चीन, तिब्बत व ताईवान के प्रति तीन पृथक राष्ट्रों के रूप में व्यवहार की नीति पर चलना आरम्भ कर देना चहिये। कश्मीर व अरुणाचल के सम्बन्ध में चीन के व्यवहार को देखते हुए यही उसका सटीक उत्तर होगा। चीन की सामरिक क्षमताओं का आधार आर्थिक है। वर्ष 2018 में भारत के आयात ही 90 अरब डॉलर (लगभग रूपये 7 लाख करोड़) के थे। अब आत्मनिभर्र भारत अभियान के फलस्वरूप घटकर अत्यन्त न्यून रह जायेंगे। जापान, अमेरिका व यूरोप सहित अधिकांश देश द्वारा आर्थिक बहिष्कार चीन को पराभव की ओर ले जायेगा। चीनी वस्तुओं के वैश्विक बहिष्कार से यह घटित होना अवश्यम्भावी है। ❑❑

चीन को सबक सिखाने के लिए

तिब्बत के साथ खुलकर खड़ा होना होगा भारत को

महाशक्ति बनने की चाह में खालिस दादागिरी पर उतरा चीन कोरोना महामारी के बीच लद्दाख की सीमा पर तनाव पैदा कर भारत को अर्दब में लेने आंख दिखाने की भरपूर कोशिश की लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन कमजोर नहीं। भारत ने न सिर्फ चीन की बीआरआई योजना का खुलकर विरोध किया, आरसीईपी को लेकर उसकी रणनीति पर पानी फेर दिया, बल्कि सीमा पर भी मजबूती से काउंटर किया। यही कारण है कि भारत के मजबूत रुख से हतप्रभ चीन को अपनी विस्तारवादी सोच को वापिस थैले में डाल बिना देरी किए पीछे हटना पडा। बीजिंग की लाल सेना के बीजमंत्र 'वार भी–व्यापार भी' पर कडा एतराज जताते हुए प्रधानमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा है कि 'दो कदम आगे और एक कदम पीछे' हटने की चीन की पुरानी चाल अब नए भारत में संभव नही है।

भारत द्वारा सामरिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाए जाने के कारण विश्व भर में लगभग अलग–थलग पड़ा चीन फौरी तौर पर भले ही पीछे हट गया है लेकिन यह नहीं माना जाना चाहिए कि वह ऐसी हालत भविष्य में फिर दोबारा नहीं करेगा। जमीन हड़पने के जुनून से पीड़ित चीन फिर वही करेगा जो कि उसकी विस्तार वादी रणनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह यात्रा के दौरान चीन की विस्तारवादी नीति का जिक्र कर दुनिया का ध्यान खींचा तब दुनिया भर में ऐसी चर्चाएं शुरू हुई कि चीन के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा उसका अपना नहीं बल्कि कब्जा किया हुआ हिस्सा है। पूर्वी तुर्किस्तान, तिब्बत, दक्षिण मंगोलिया, हांगकांग और मकाऊ जैसे 6 देश ऐसे हैं जिन पर चीन कब्जा जमा चुका है अथवा उस पर अपना हक मानता है।

अब समय आ गया है कि भारत चीन को कडी व्यापारिक चुनौती देने के साथ–साथ अपनी विदेश नीति में आवश्यक बदलाव कर तिब्बत के साथ खुलकर खड़ा हो।

– अनिल तिवारी

गलवान घाटी में हुए हालिया सैन्य संघर्ष, जिसमें हमारे बीस सैनिकों को शहादत देनी पड़ी, से यह साफ हुआ कि पिछले लगभग चार दशकों से हमारे हुक्मरान चीन को लेकर आत्मभ्रम के शिकार रहे हैं। भारतीय कूटनीति जियांग जेमिन,हू चिंताओं से लेकर शी जिनपिंग तक के विस्तारवाद को समझने में विफल रही। चीन में जिनपिंग वर्ष 2013 में सत्ता में आए थे। भारत में नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में। सत्ता पर काबिज होते ही जिनपिंग आर्थिक विस्तारवाद की आड़ में चीन का भौगोलिक विस्तार बेल्ट एंड रोड पहल के तहत शुरू कर दिया। एशिया से अफ्रीका तक आर्थिक निवेशों की झड़ी लगा दी। चीनी सैन्यअडडे बनने लगे। वर्ष 2017 में जिबूती में सैन्य अड्डा बनने के बाद चीन का दबदबा अदन की खाड़ी,

लाल सागर से लेकर हिंद महासागर तक बढ़ा। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन ने ले लिया।

मालूम हो कि चीन की जमीनी सीमा 14 देशों से लगती है। सारे पड़ोसियों से उसका सीमा विवाद रहा है। उसकी नीति हमेशा दबंगई की रही है। सीमा विवाद होने पर वह अपनी विचारधारा की भी तिलांजलि देता रहा है। चीन ने अपने कम्युनिस्ट साथी देश रूस और वियतनाम को भी नहीं बख्शा। चीन का रूस से जमीन को लेकर युद्ध हुआ। सोशलिस्ट वियतनाम से रार हुई। समुद्री क्षेत्र में दूरी पर स्थित इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, वियतनाम और मलेशिया के द्वीपों को चीन अपना हिस्सा बताता रहा है। आदि–आदि।

चीनी विस्तारवाद के लंबे चौड़े इतिहास के बाद भी भारत को आखिरकार कैसी गलतफहमी रही कि चीन भारत के साथ दोस्ताना वह व्यवहार करेगा। भारत की लंबी सीमा चीन से जुड़ती है। तिब्बत के साथ–साथ लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान को भी चीन अपना हिस्सा मानता है। चीन की यह सारी दावेदारी बिना साक्ष्य और दादागिरी की दावेदारी है। चीन के पक्ष में कोई अंतरराष्ट्रीय संधि नहीं है। कोई दस्तावेजी सबूत उस के पक्ष में नहीं है।चीन अपने हिसाब से दावे करता है और समय–समय पर साक्ष्य भी गढता रहा है। अपने पुराने राजवंशों की दंत कथाओं और उनके अनुकूल लिखे इतिहास के आधार पर भूगोल की दावेदारी करता है। बताते हैं कि किसी जमाने में चीन के मिंग वंश ने वियतनाम के कुछ भाग पर शासन किया था बस उस इसी आधार पर वह वियतनाम हथियाना चाहता है। यही हाल मंगोलिया को लेकर है।

भारत के विशाल आकार और यहां की युवा मेधा, ज्ञान शक्ति के उभार को चीन अपने लिए चुनौती मानता है। ज्ञात हो कि लगभग 300 साल पहले तक भारत और चीन विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार होते थे। बीसवीं सदी के मध्य तक दोनों देशों में तरक्की की क्षमता थी। हालांकि उस समय तक दोनों बेहद गरीब देश हो गए थे। उसी समय से चीन को आशंका थी कि भारत भविष्य में उसे कड़ी टक्कर दे सकता है। यही कारण है कि जब हम हिंदी चीनी भाई–भाई का नारा लगा रहे थे तो चीन भारत ही नहीं पूरे एशिया में वर्चस्व जमाने की दिशा में काम शुरू कर चुका था। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए तिब्बत और झिनझियांग पर कब्जा कर लिया था। इसी के साथ भारत और चीन इतिहास में पहली बार पड़ोसी देश बन गए। बाद में वह चुपके से अक्साई चीन, लद्दाख के हिस्से पर काबिज हो गया ताकि वह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तिब्बत और झिनझियांग को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कर सकें। भारत को पता चला तो विवाद शुरू हुआ फलस्वरुप दोनों देशों के बीच सन 1962 का युद्ध हुआ। हालांकि चीन ने आसानी से युद्ध जीत लिया लेकिन ज्यादा क्षेत्र पर काबिज नहीं हो सका। केवल लद्दाख के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर पाया। अक्साई चीन तो पहले से ही उसके कब्जे में था।

चीन को यह आभास है कि भारत अब एक मजबूत देश है। भारत केबाजार की ताकत भी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो चुकी है। भारतीय युवा शक्ति को चुनौती देना आसान नहीं है, इसलिए चीन भारत को कमजोर करने का हर संभव प्रयास करता रहता है। चीन सीमा पर तनाव पैदा करने, गाहे–बगाहे गीदड भभकी देने, भारतीय बाजार में हिंसक ऋण निवेश करने, आवारा पूंजी को प्रश्रय देने की कुटिल चाल चलता रहा है।

इतना ही नहीं बांग्लादेश की आजादी के बाद से ही चीन भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान को उकसाने में जुटा रहता है। चीन ने पाकिस्तान को ने केवल सैन्य समर्थन दिया है बल्कि परमाणु तथा मिंसाइल क्षेत्र में भी सहयोग दे रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ने की नीति अपनाई तो चीन ने उसका साथ दिया तथा अजहर मसूद जैसे आतंकियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध लगाने संबंधी फैसले नहीं होने दिए।

देर से ही सही, गलवान की हालिया घटना के बाद नई दिल्ली की निंद्रा टूटी है। प्रधानमंत्री ने लेह की ऊंचाई से कहा कि चीन एक विस्तार वादी देश है। उसके साथ अब आगे टकराव और लेन–देन का सिलसिला नहीं चलेगा। हिंदी चीनी भाई–भाई के फरेब और वैश्वीकरण की आंधी में आर्थिक चकमक की सपनीली दुनिया से बाहर निकलकर सार्वभौम भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता को आगे करने पर जोर दिया है। चीन को आर्थिक रुप से जवाब देने के लिए भी देश के लोगों में जागरूकता बढ़ी है। स्वदेशी जागरण मंच के आह्वान पर देश भर में चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार हो रहा है।

भारत को लद्दाख गिलगित और बलिदान के को लेकर गंभीर प्रयास करने चाहिए। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड गठित किया है। इससे समान विचार वालों को जोड़ने का प्रयास करना होगा वरना चीन एक–एक कर सबके समक्ष चुनौती पेश करता रहेगा। वैश्विक शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए सभी देशों को चीन की विस्तार वादी नीतियों के विरोध में खड़ा होना होगा और भारत की इस में विशेष भूमिका अवश्यम्भावी है। अब समय आ गया है कि भारत चीन को कडी व्यापारिक चुनौती देने के साथ–साथ अपनी विदेश नीति में आवश्यक बदलाव कर तिब्बत के साथ खुलकर खड़ा हो। ❑❑

चीन-भारत संघर्ष के तात्कालिक कारण

ऐसे समय में जब दुनिया 'चीनी वायरस' कोविड–19 से जूझ रही है, मौतों का आंकड़ा नई ऊंचाइयां छू रहा है, वैश्विक अर्थव्यवस्था मंद पड़ चुकी है, दुनिया अपने–अपने दायरे में सिमटकर विश्व–व्यवस्था पर पुनर्विचार कर रही है, विश्व में चीन के प्रति नाराज़गी नफरत की हद तक जा चुकी है, तो दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए चीन ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

चीन से तनातनी अचानक शुरू नहीं हुई, इसके स्थानीय और क्षणिक कारण नहीं अपितु वैश्विक कारण हैं। अमेरिका में बढ़ती मौतों का आंकड़ा देखकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपनी गिरती प्रतिष्ठा को रोकने के लिए चीन को सबक सिखाने के लिए अपनी रणनीति पर कार्य करना शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग संधि की है, ताकि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत को रोका जा सके। इस संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया और भारत जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का प्रयोग कर सकेंगे। अमेरिका–जापान–ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच सुरक्षा को लेकर चतुष्कोणीय समझौता भी विस्तारवादी चीन की घेराबंदी की कोशिश है।

इस बीच अमेरिका ने जी.–7 का विस्तार जी.–11 के रूप में करने तथा इसमें भारत, रूस, दक्षिण कोरिया तथा ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने की मंशा जाहिर करके चीन को चेतावनी देने का कार्य किया है। इससे जाहिर होता है कि वैश्विक स्तर पर चीन को घेरने के प्रयासों में विश्व की नजर भारत पर है। कोरोना के कारण वैश्विक स्तर पर "मेड इन चाइना" का बहिष्कार होने लगा, तब कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को चीन से स्थानांतरित करने का मन बना लिया है। जापान जैसे कुछ देशों ने तो अपनी कंपनियों को चीन से बाहर जाने के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा भी की

देश के स्वाभिमान तथा विश्व की सबसे युवा आबादी को रोजगार तथा स्वाभिमान की राह स्वदेशी से ही आसान होगी। चीन की चालबाजियों को कड़ा और विवेकपूर्ण जवाब देकर ही भारत विश्व में अपनी अलग पहचान बना सकता है।
– **दुलीचन्द कालीरमन**

है। विश्व में बन रहे माहौल तथा कोरोना वायरस को अवसर में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने "आत्मनिर्भर–भारत" पर कार्य करना शुरू कर दिया है। शीर्ष स्तर पर इससे पहले स्वदेशी की इस भावना को कभी स्वीकार नहीं किया गया था।

यह सब कुछ इतनी जल्दी–जल्दी हो रहा था कि चीन का परेशान हो जाना लाज़िमी था। चीन नहीं चाहता था कि उसके पड़ोस में भारत आर्थिक–सामरिक उन्नति करें। परिणामस्वरुप उसने भारत के चिर–परिचित पारंपरिक मित्र नेपाल को भड़काना शुरू कर दिया। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार एक तरह से 'चीन का तोता' बन चुकी है। चीन के उकसावे में आकर उसने भारत के लिपुलेख, काला पानी तथा लिपीयधुरा को अपने मानचित्र में दिखाकर नए नक्शे को नेपाली संसद की मंजूरी दिला दी। पाकिस्तान पहले से ही 'पाक अधिकृत कश्मीर' के छिन जाने के डर से डरा बैठा था। जब से 'अनुच्छेद–370' हटा तथा 'जम्मू–कश्मीर पुनर्गठन विधेयक' आया है, तब से चीन को भी लगने लगा था कि अगर भारत 'पाक अधिकृत कश्मीर' को वापिस ले लेता है तो उसका "चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे" पर खर्च हुआ अरबों डालर व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की गुलामी का रास्ता "बीआरआई" पाक अधिकृत कश्मीर से होकर ही जाता है।

> **चीन का नया हथियार उसका सांस्कृतिक हमला है। जिसके माध्यम से वह पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों को चीनी भाषा पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।**

चीन यह नहीं चाहता था कि कोरोना के बाद बदली हुई परिस्थितियों का लाभ भारत को मिले। सारा विश्व जब मई में कोरोना से लड़ रहा था तो चीन ने अपने सैनिकों को युद्ध अभ्यास के नाम पर गलवान घाटी में इकट्ठा करना तथा निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया। भारत की 'दौलत बेग ओल्डी' में बनी रणनीतिक बढ़त को रोकने के लिए चीन निरंतर प्रयास कर रहा है। 15 जून के खूनी संघर्ष की घटना भी चीन की इसी रणनीति का अंग है। चीन भारत को दुनिया भर में निवेशकों तथा चीन से आने वाली कंपनियों की नजर में अस्थिर तथा युद्ध का भय दिखाना चाहता है ताकि कोरोना का यह संक्रमणकाल गुजर जाए और भारत इस मौके का फायदा न उठा सके।

चीन विश्व में कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहा है। अपने सस्ते माल के कारण वह अमेरिका जैसी कई अर्थव्यवस्थाओं को पंगु बना चुका है। जिसमें उन देशों में बेरोजगारी की दर उच्चतम स्तर तक जा चुकी है तथा स्थानीय जनता में आक्रोश कई अन्य रूपों में फूट रहा है। चीन की लड़ाई का एक अन्य पहलू उसकी कर्जदार बनाने की नीति है। जिसमें वह विश्व के कई छोटे देशों को अपने जाल में फंसाकर उसके संसाधनों पर कब्जा कर चुका है। वहां की सरकारें भी चीनी तोता बन चुकी हैं। भारत के कई पड़ोसी देश इस श्रेणी में आते हैं।

चीन का नया हथियार उसका सांस्कृतिक हमला है। जिसके माध्यम से वह पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों को चीनी भाषा पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। नेपाल तथा पाकिस्तान की सरकारें भी खुश हैं क्योंकि चीनी भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों को वेतन चीन देता है। एक कम्युनिस्ट देश चीन से वेतनभोगी अध्यापक पाकिस्तान और नेपाल के बच्चों को चीनी भाषा के माध्यम से कौन सी विचारधारा पढ़ाएंगे, यह अंदाजा लगाना कठिन नहीं है।

भारत इन सब चुनौतियों का सामना डटकर कर रहा है। स्वदेशी व 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना सिर्फ क्षणिक न होकर सरकार की नीतियों में स्पष्ट नजर आनी चाहिए। सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में इसकी कुछ झलक दिखाई भी देती है। देश के स्वाभिमान तथा विश्व की सबसे युवा आबादी को रोजगार तथा स्वाभिमान की राह स्वदेशी से ही आसान होगी। चीन की चालबाजियों को कड़ा और विवेकपूर्ण जवाब देकर ही भारत विश्व में अपनी अलग पहचान बना सकता है। ❑❑

चीन से युद्ध के अलावा, आर्थिक मोर्चे पर भी नया फ्रंट जरूरी

क्या भारत को चीन से युद्ध के अलावा अलग आर्थिक मोर्चे पर कोई नया फ्रंट खोलना चाहिए, क्योंकि जितनी तेजी से विश्व के आर्थिक हालात बदल रहे हैं, उसमें चीन के साथ लंबे टकराव में भारत यदि उलझा रहा, तो आर्थिक क्षेत्र में जो अवसर बाकी देशों को मिल रहे हैं, उससे वंचित रह जाएगा।

अब यह स्पष्ट है कि चीन के साथ कोई भी प्रमुख देश व्यापारिक संबंध रखना नहीं चाहता। चाहे वह अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या यूरोपीय यूनियन हो, सबके मन खट्टे हैं और सब चीन से छुटकारा पाना चाहते हैं। और यह भी तय है कि चीन जितना बड़ा बाजार और इंफ्रास्ट्रक्चर कोई देश दुनिया को दे सकता है तो वह भारत ही है। इसलिए भारत के लिए यही उपयुक्त समय है कि पूरी दुनिया को यह कहे कि चीन से अपनी फैक्ट्री या अपना बिजनेस समेटने वाले हमारे यहां आ सकते हैं।

बिना चीन के भी भारत कर सकता है आर्थिक तरक्की

चीन के साथ युद्ध की प्रबल आशंका के बीच कुछ हलकों से यह बात फैलाई जा रही है कि चीन का आर्थिक बॉयकाट करना संभव नहीं है, क्योंकि चीन पूरी दुनिया का मैन्यूफैक्चरिंग हब बन चुका है और हर उस देश को चीन से या तो कच्चा माल चाहिए या फिर सस्ता उत्पाद जो अपनी अर्थव्यवस्था को गति देना चाहते हैं।

यह देखते हुए कि लद्दाख में चीन की आक्रामकता के बाद पूरे देश में चीन के उत्पाद को लेकर एक रोष है और लोग बायकॉट चीन का अभियान चला रहे हैं, चीन बहुत परेशान हो रहा है और बार–बार यह कह रहा है कि चीन के खिलाफ भारत में राष्ट्रवाद की जो लहर उठ रही है वह अतंतः भारत को ही नुकसान पहुंचा रही है। कुछ भारतीयों द्वारा भी यह भ्रम

एक बार हम चीन के साथ व्यापार करना बंद करने का निश्चय कर ले तो शुरू में जरूर जीवन स्तर में कमी और कुछ सुविधाओं में कटौती का सामना करेंगे, लेकिन फिर निश्चित रूप से हमारे पास अधिक नौकरियां होंगी और अधिक महत्वपूर्ण रूप से आशा और अवसर की भावना होगी।
– विक्रम उपाध्याय

फैलाया जा रहा है कि चीन के बिना भारत आर्थिक प्रगति नहीं कर सकता।

चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के कभी सलाहकार रहे सुधीन्द्र कुलकर्णी का एक साक्षात्कार 24 जून को छापा है, जिसमें सुधीन्द्र कुलकर्णी को यह कहते हुए दिखाया गया है कि भारत ने 'बायकॉट चीन' का मूर्खता भरा अभियान शुरू किया है। क्योंकि हमारे ऊपर यह दायित्व है कि विश्व के दो बड़े देश आपस में सहयोग कर लोगों के लिए समृद्धि लाएं और विश्व में शांति स्थापित करें। लेकिन न तो ग्लोबल टाइम्स ने और न सुधींद्र कुलकर्णी ने यह समझाने की कोशिश की है कि भारत के 20 सैनिकों को धोखे से मारने वाला चीन इसके बाद भी भारत से ही आर्थिक सहयोग की अपेक्षा रखता है। कई कॉरपोरेट घरानों ने भी टोटल बॉयकॉट की कॉल को प्रायोगिक नहीं माना है। चीन के साथ कई परियोजनाओं में काम कर रहे लार्सन एंड टुर्बो के सीईओ एस एन सुब्रमनियम, ब्लू स्टार के थियागराजन भी उनमें हैं।

दुनिया भारत और चीन के बीच संभावित युद्ध की परिणती देखने के बाद कोई फैसला नहीं करेगी, क्योंकि कोरोना के थमने के बाद पूरे विश्व में यह होड़ मचेगी कि कौन कितनी जल्दी अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सफल होता है। विश्व की तमाम कंपनियां फैसला कर रही है और अपनी-अपनी प्रोडक्शन यूनिट को तेजी से चीन से हटा भी रही हैं। लेकिन इन सबका फायदा भारत को अभी तक नाममात्र का ही मिला है।

वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और ताइवान सबसे अधिक फायदा उठा रहे हैं। सबसे दुख की बात यह है कि भारत अभी तक उन कंपनियों का डेस्टिनेशन नहीं बन पाया है जो चीन से उठकर, एशिया के देश में आ रही हैं। साउथ ईस्ट एशिया में भी म्यामार, फिलीपींस और बांग्लादेश यह अवसर उठाने में भारत से आगे हैं।

भारत को चीन के साथ किसी भी युद्ध से निबटने की तैयारी के साथ साथ नया फोकस एरिया इकोनामिक और बिजनेस एनवायरमेंट को ठीक करने का होना चाहिए। भारत के पास विशाल लैंड पुल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ओपन बाजार है, सस्ती लेबर है और सबसे बड़ी बात एक स्थाई सरकार और स्थिर नीतियां हैं। भारत को तत्काल अपनी औद्योगिक नीति, आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स नीति और नई स्टार्टअप नीति में बदलाव करना चाहिए। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हम चीन को टक्कर दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की पहल

उत्तर प्रदेश की तरह हमें लगभग सभी राज्यों में पुरानी मशीनरी को लाने की अनुमति देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश ने 40 प्रतिशत तक पुरानी मशीनरी को लाने की अनुमति दे दी है। यूपी की एक और पहल विदेशी कंपनियों को भारत लाने में सहायक हो सकती है और वह है श्रमिकों का कौशल मूल्यांकन के आधार पर रजिस्ट्रेशन। स्कील मैपिंग एक मेजर अट्रैक्शन हो सकता है। चीन की ही तरह भारत के राज्य अपने यहां प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेक्टर बना सकते हैं। जैसा कि हमने आईटी के कई हब बनाए हैं।

विदेशी कंपनियों के लिए चीन का आकर्षण सिर्फ इतना ही था कि वहां उत्पादन लागत कम हैं और कच्चे माल की भरपूर उलब्धता है। लेकिन भारत में यह स्थिति नहीं है। कुछ सालों से भारत भी कई औद्योगिक उत्पादनों के लिए चीन से कच्चा माल खरीदता रहा है। चीन भारत में आने वाली कंपनियों के लिए यह समस्या पैदा कर सकता है कि वह कच्चे माल की सप्लाई ही न करे। लेकिन भारत के पास यह क्षमता है कि वह कच्चे माल या कंपोनेंट की आपूर्ति घरेलू क्षमता में विस्तार कर बढ़ा दे। हालांकि इसमें समय लग सकता है, लेकिन कहीं न कहीं से आपको शुरूआत तो करनी ही पड़ेगी।

चीन बार-बार यह कह रहा है कि भारत उससे प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकता, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था भारत से पांच गुनी है। यह चीन द्वारा भारत को डराने का एक तरीका भी है। कई आर्थिक विशेषज्ञ यह बताते हैं कि चीन की जीडीपी एक बार नीचे गई नहीं कि फिर यह संभल नहीं पाएगी। क्योंकि जीडीपी की गणना आर्थिक गतिविधियों से ही होगी। जो इस समय ठप दिखाई दे रही है। फिर दुनिया को इस बात की भी आशंका है कि चीन की वाकई जीडीपी ग्रोथ रेट उतनी है की नहीं, जितनी दावा करता है।

दि फाइनेंसियल टाइम्स का कहना है कि चीन की जीडीपी उसके दावे से 12 प्रतिशत कम है। विशेषज्ञ यह भी कह रहे हैं कि यदि चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं होती है, और भारत में 6 प्रतिशत की भी वृद्धि होती है तो भारत अगले दस साल में चीन की बराबरी पर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि चीन को लेकर विश्व बिरादरी का यह रूख बरकरार रहे और भारत में स्थिरता बनी रहे।

कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि एक बार हम चीन के साथ व्यापार करना बंद करने का निश्चय कर ले तो शुरू में जरूर जीवन स्तर में कमी और कुछ सुविधाओं में कटौती का सामना करेंगे, लेकिन फिर निश्चित रूप से हमारे पास अधिक नौकरियां होंगी और अधिक महत्वपूर्ण रूप से आशा और अवसर की भावना होगी। इसी तरह से चुनौतियों से देश टिक सकता है, क्योंकि यह हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा और मेहनत से ही समृद्धि आएगी। ❑❑

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार का पहिया धीरे–धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। देश में रबी की बंपर पैदावार के बाद फसलों के लिए किसानों को लाभप्रद न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला है। सरकार द्वारा किसानों को दी गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, गरीबों के जनधन खातों में नगद रुपया डालने जैसे कदमों से किसानों के हाथ में जरूरी धनराशि पहुंची है। मार्च 2020 में हुए लॉकडाउन के बाद से अब तक किसानों के पास करीब 1.33 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुके है। इसी अवधि में 8 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर के साथ–साथ मनरेगा के तहत करीब 17 हजार 600 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। कुछ शहराती चिर असंतुष्टों की नकारात्मक स्थितियों के बरक्स गांव से सुखद समाचार आ रहे हैं। ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ने से उन क्षेत्रों में उपभोग की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में उर्वरक, बीज, खाद, रसायन, ट्रेक्टर एवं कृषि उपकरण जैसी वस्तुओं के साथ–साथ उपभोक्ता वस्तुओं के मांग में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है। अच्छे मानसून के आगमन से आर्थिक खुशहाली के संकेत मिल रहे हैं।

हमारे देश की रीढ़ कृषि बहुत हद तक मानसून पर निर्भर है। देश में मानसून अच्छा रहता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में चमक आ जाती है और कई बार देखा गया है कि खराब मानसून अर्थव्यवस्था में मुश्किलें बढ़ा देता है। अच्छा मानसून हमारे यहां आर्थिकी के साथ–साथ सामाजिक खुशहाली का भी कारण माना जाता है। क्योंकि देश में आधे से अधिक खेती सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर होती है। चावल, मक्का, गन्ना, कपास और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए बारिश बहुत जरूरी है। हालांकि हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद का 17 प्रतिशत योगदान कृषि क्षेत्र का है लेकिन कुल आबादी का लगभग 60 प्रतिशत इस क्षेत्र पर आश्रित है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत है।

मालूम हो कि मानसून का प्रभाव में केवल देश के करोड़ों लोगों की रोजी–रोटी और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है बल्कि समाज, कला, संस्कृति और लोक जीवन पर भी इसका सीधा असर दिखाई देता है। क्योंकि कई महत्वपूर्ण मुद्दों को जैसे टेक्सटाइल,

यकीनन कोविड–19 एक आपदा की तरह आया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे एक अवसर की चुनौती की तरह लेने का आह्वान किया है। उम्मीद करें 2020 के अच्छे मानसून का परिदृश्य तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए सरकार की घोषणाओं के कारगर क्रियान्वयन से करोड़ों किसानों के घर खुशहाली दस्तक देगी।

– स्वदेशी संवाद

सोयाबीन, शक्कर मिल, दाल मिल, आदि सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है और कई उद्योग अप्रत्यक्ष तौर पर कृषि उत्पादों पर आश्रित है। इसलिए देश के लिए मानसून की बड़ी अहमियत है।

चालू वित्त वर्ष 2020 में अच्छे मानसून का महत्व इसलिए भी प्रासंगिक है कि कोविड–19 की महामारी से निपटने के लिए उठाए गए लॉकडाउन के कदम के चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था लगभग चरमरा सी गई है। अनलॉक फेज शुरू होने के पहले ग्रामीण भारत दोहरी मार झेल रहा था। एक तरफ ग्रामीणों की कमाई यातायात बंद होने से प्रभावित हुई थी, वहीं दूसरी तरफ शहरों में रहने वाले उनके परिजन जो अपनी शहरी कमाई का कुछ हिस्सा गांव के लिए भेजते थे, वह स्वयं कोविड की वजह से अपना काम गंवाकर गांव में लौट आए थे। भारी संख्या में प्रवासियों के लौटने से गांव की मैरिज इकोनॉमी अचानक शून्य के स्तर पर आ गई थी।

भारत एक उत्सव प्रधान देश है। हमारे सभी उत्सव समाज को हर दृष्टि से जोड़ते हुए मजबूती प्रदान करते हैं। खासकर शादी विवाह की रस्मों की ऐसी बुनावट की गई है जिसमें हर तबके को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से मजबूत करने की व्यवस्था है। नाच, बाजा, शामियाना, बढ़ई, लौहार, कुम्हार, पुरोहित आदि अनेक वर्ग के लोग अपनी वर्ष भर की आजीविका इसी के जरिए अर्जित करते रहे हैं। उनके समक्ष संकट की स्थिति थी। कृषि क्षेत्र ने इस संकट को बहुत हद तक संभाला है। अब अच्छे मानसून से ऐसे परिवारों की खुशियां उम्मीदें लेकर आई है। प्रवासी परिजनों द्वारा गांव में किए जा रहे श्रम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ मिलने लगा है। महामारी के दौरान ही सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक पैकेज का लाभ ग्रामीणों को मदद करने में सहायक बना है। गरीबों के लिए नवंबर तक मुफ्त राशन की योजना का लाभ एक बडी आबादी को मिल रहा है। वही खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण किसानों की आय में वृद्धि हुई है।

भारत एक उत्सव प्रधान देश है। हमारे सभी उत्सव समाज को हर दृष्टि से जोड़ते हुए मजबूती प्रदान करते हैं। खासकर शादी विवाह की रस्मों की ऐसी बुनावट की गई है जिसमें हर तबके को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से मजबूत करने की व्यवस्था है।

गत दिनों सरकार ने 17 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 2 से लेकर 7.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। विशेष रूप से खरीद की मुख्य फसल धान के लिए 2.89 से 2.92 प्रतिशत, तिलहनों के लिए 2.07 से 5.26 प्रतिशत तथा बाजरे के लिए 7.5 प्रतिशत एमएसपी में वृद्धि की गई है। नई एमएसपी बढ़ोतरी में मोदी सरकार द्वारा किसानों को फसल लागत से 50 प्रतिशत अधिक दाम देने की नीति का पालन करने के लिए कहा गया है। नई कीमत उत्पादन लागत से 50 से 83 प्रतिशत अधिक होगी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को 4 प्रतिशत ब्याज पर 3 लाख रूपये तक का कर्ज सुनिश्चित किया जाना भी किसानों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा।

प्रकृति की मेहरबानी और सरकार के लगातार प्रयास से ग्रामीण भारत की आर्थिक की अच्छी दिशा में है। ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और चमक लाने के लिए अच्छे मानसून का लाभ लेने के साथ–साथ हमें कई एक बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। सरकार द्वारा कृषि उपज का अच्छा विपणन सुनिश्चित करना होगा। इससे ग्रामीण इलाकों में मांग में और अधिक वृद्धि की जा सकेगी। ग्रामीण मांग बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विस सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे। किसानों के खरीफ सीजन के मद्देनजर कृषि उत्पादन के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराना होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से गांव में लौटे श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन हेतु अतिरिक्त फंड का आवंटन करना होगा। मनरेगा के उपयुक्त क्रियान्वयन पर भी सचेत रूप से नजर रखनी होगी।

सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उन्नत कृषि, शीत भंडारगृह, पशुपालन, डेयरी उत्पादन तथा कृषि प्रसंस्करण उद्योगों से संबंधित जो घोषणा की है उन्हें शीघ्रतापूर्वक कारगर तरीके से लागू किया जाना चाहिए। विशेष रूप से देश में पहली बार कृषि सुधार के लिए जो तीन ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करने के फैसले से अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू और प्याज की कीमतें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति को छोड़कर भंडारण सीमा से स्वतंत्र हो जाएगी। ऐसे में जब किसान अपनी फसल को तकनीक एवं वितरण नेटवर्क के जरिए देश और दुनिया भर में कहीं भी बेचने की स्थिति में होंगे तो इससे निश्चित रूप से किसानों को उपज का बेहतर मूल्य हासिल होगा। यकीनन कोविड–19 एक आपदा की तरह आया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसे एक अवसर की चुनौती की तरह लेने का आह्वान किया है। उम्मीद करें 2020 के अच्छे मानसून का परिदृश्य तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए सरकार की घोषणाओं के कारगर क्रियान्वयन से करोड़ों किसानों के घर खुशहाली दस्तक देगी। ❑❑

जैविक खेती, स्थानीयता और एकजुटता वाली अर्थव्यवस्था के आधार पर

आत्मनिर्भर बीज स्वराज और अन्न स्वराज की ओर भारत

भारत में ब्रितानी उपनिवेशवाद के चलते खेती पर शोषणकारी 'लगान' थोपा गया। इस अन्यायी व्यवस्था ने भारत पर भोजन का संकट खड़ा कर दिया था। इस 'लगान' के कारण हमने 1942 में बंगाल का भीषण अकाल झेला। इस अकाल में 20 लाख लोग मारे गये थे। और भारत में ब्रितानी हुकूमत के दौरान 6 करोड़ लोग मारे गए।

एक प्रार्थना सभा के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था– ''हमें स्वयं–सहायता और आत्मनिर्भरता के सबक को आत्मसाथ करना होगा। इस सबक के बल पर हम विदेशों पर निर्भरता और वर्तमान दिवालियापन की स्थिति से मुक्त हो सकेंगे। मैं यह बात अहंकारवश नहीं कह रहा। मैं यह बात तथ्यों के आधार पर रख रहा हूं। हम कोई छोटी जगह नहीं हैं जो भोजन के लिए किसी बाहरी देश की मदद पर जिएं। हम एक उपमहाद्वीप हैं। हम 40 करोड़ (अब 130 करोड़) लोगों का देश हैं। हमारे देश में शक्तिशाली नदियां बहती हैं। हमारे खेत समृद्धि की विविधता से लबालब हैंकृ''

आजादी के बाद हमारी खेती शोषणकारी पंजों की गिरफ्त से मुक्त हो गई, तो हमारी कृषि की संरचना पहले जैसे रूप में आने लगी। पुनर्योजी अर्थव्यवस्था की यह पहल ने हमें आत्मनिर्भरता की ओर ले गई। आत्मनिर्भरता की दस्तक ने देश की गरीबी, जर्जर होते खेत, टूटे हुए पोषक तत्वों और जल–कल के टूटते चक्र की मरम्मत की। उन्हें नव जीवन दिया। किसानों को उनकी मेहनत की कमाई का वचन/गांरटी दी। इस आत्मनिर्भरता के कदम ने सभी को पहले भोजन की उपलब्धता को प्राथमिकता दी। औपनिवेशिक नीति वाली औद्योगिक खेती आधारित नकदी फसलों और कच्चे माल को प्राथमिकता नहीं दी।

27 सितंबर 1951 की बात है। श्री. के.एम. मुंशी भारत के पहले कृषि मंत्री थे। भारतीय खेती की पुनर्स्थापना पर एक कार्यक्रम में राज्य के कृषि निदेशकों से श्री मुंशी ने कहा– आप

आत्मनिर्भरता की दस्तक ने देश की गरीबी, जर्जर होते खेत, टूटे हुए पोषक तत्वों और जल–कल के टूटते चक्र की मरम्मत की। उन्हें नव जीवन दिया। किसानों को उनकी मेहनत की कमाई का वचन दिया है।
– डॉ. वंदना शिवा

योजना बनाते वक्त भारत की मिट्टी, फसलों और जलवायु की विविधता को ध्यान में रखें। भारतीय खेती के उत्थान के लिए योजना का रेखांकन प्रत्येक गांव और आवश्यक हुआ तो प्रत्येक खेत को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। जब आप योजना बना रहे हों तो उसे नीचे से ऊपर की तरफ आकार दें।

श्री मुंशी ने कहा– ''जब आपकी अध्यक्षता में गांव के जीवन–चक्र के जल और पोषण संबंधी दोनों पहलूओं पर अध्ययन हो। आप यह भी पता करें कि जीवन के चक्र में कहां गड़बड़ी आ गई है। तब आप इस चक्र में सुधार लाने के सभी जरूरी कदमताल करें। जो लोग यह मानते है कि गांवों के जीवन चक्र की बाहाली न सिर्फ देश की स्वतंत्रता और खुशहाली के लिए जरूरी है, बल्कि देश के अस्तित्व के लिए भी परम आवश्यक है, उनके लिए जीवन चक्र की आरोग्यता को वापस लाना असंभव नहीं।''

प्रकृति के चक्र के नवसृजन की प्रक्रिया और भोजन तथा खेती के प्रति हमारी आत्मनिर्भरता को रासायनिक खेती आधारित हरित क्रांति और कार्पोरेट संचालित वैश्वीकरण (जिसे मुक्त व्यापार कहा गया) ने मटियामेट कर दिया।

पृष्ठभूमिः

हरित क्रांति, भोजन के औद्योगिकीकरण और कृषि के वैश्वीकरण का आजीविका, भुखमरी और बीमारी के संकट को न्यौता देने में योगदान– हरित क्रांति का मॉडल ऊर्जा की सघनता, जल की सघनता और रसायनिकों के अंधाधुंध प्रयोग पर आधारित था। इस मॉडल ने स्वतंत्रता के बाद पुनर्स्थापना की नीतियों से होने वाले लाभ को कम किया। मिट्टी के क्षरण और भूमि कटाव को बढ़ावा दिया। भारत की लबालब जैव विविधता को खत्म करने का काम किया। देश में जल संकट को बढ़ावा दिया। जलवायु परिवर्तन में तेजी पैदा की और असाध्य बीमारियों को उत्पन्न करने में योगदान दिया।

1991 से रासायनिक खेती के साथ खाद्य और कृषि वैश्वीकरण का समागम हुआ। इस तिकड़ी ने औद्योगिक खाद्य प्रसंस्करण के लिए हमारी मुख्य फसलों के साथ कच्चे माल की वस्तुओं के जैसा व्यवहार किया। यह सरासर गलत था। इस वजह से किसानों की निर्भरता महंगे बीजों के साथ खेती से संबंधित दूसरे आदान जैसे रासायनिक खाद, कीटनाशक और शाकनाशकों पर बढ़ने लगी। किसानों की खेती पर लागत अधिक और उत्पादन का मूल्य कम होने लगा और किसान कर्ज के दलदल में फंस गया। इस तरह से अन्नदाता के हाथों से बीज स्वराज और अन्न स्वराज छिनता गया। और इस कुचक्र के ताने–बाने ने देश में कृषि संकट को बढ़ावा देने में भरपूर योगदान दिया।

झूठी उत्पादकताः

किसानों का विस्थापन, आजीविका का सत्यानाश और भुखमरी एवं कुपोषण की कुंजीः नव उदारवादी वैश्वीकरण से प्रेरित औद्योगिक खेती ने किसानों को अपनी ही जमीन में शरणार्थी बना दिया। हेरफेर कर किसानों को उत्पादकता की मृग–मरीचिका में बहलाया गया, जैसे लोगों को रेगिस्तान में पानी होने का भ्रम होता है। उन्हें इस भ्रम के फंसाया गया कि वे अधिक उत्पादन कर भुखमरी को कम कर रहे हैं।

किसानों को यह बात समझ में नहीं आने दी गई कि रासायनिक खेती में उत्पादन के लिए ऊर्जा की खपत की एवज में उनका उत्पादन कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्होंने अपने खाते से जितना धन लगाया उत्पादन उससे कहीं कम हुआ। किसानों को समझ नहीं आया कि वे नकारात्मक आर्थिक व्यवस्था के चक्र में फंस गये हैं। उन्होंने दस यूनिट ऊर्जा की खपत पर मात्र एक यूनिट उत्पादन प्राप्त किया। उन्हें यह बात नहीं समझाई गई। इस तरह से औद्योगिक खेती छद्म उत्पादकता की आढ़ में पारिस्थितिक संकट, बेरोजगारी, भुखमरी और कुपोषण के संकट को पैदा कर रही है।

खेती से विस्थापित किसान यानी कृषि शरणार्थी जिनका खेती से मोहभंग हो गया था, अब कोरोना लॉकडाउन की वजह से अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं। उन्हें प्रवासी श्रमिक कहना अनुचित है क्योंकि वे भारतीय नागरिक हैं और वे देश के किसी भी कौने में जाने, वहां आजीविका उत्पादन हेतु कार्य करने और वहां से घर वापस आने के लिए स्वतंत्र हैं। वे विस्थापित कार्यकर्ता हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 48.2 करोड़ श्रमिक थे। इनमें से औपचारिक क्षेत्र में मात्र 3.3 करोड़ श्रमिक हैं। बाकी 93 प्रतिशत लोग असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। जनगणना के अनुसार 11.9 करोड़ किसान, 14.4 करोड भूमिहीन कृषि श्रमिक और 21.9 गैर–कृषि श्रमिक हैं। 80 प्रतिशत शहरी श्रमिकों ने नौकरियां खो दीं और गांवों की तरफ पलायन शुरू कर दिया है। ये हमारी अर्थव्यवस्थ्या की नींव को मजबूत करने वाले लोग हैं। इन कामकाजी लोगों के हाथों से रोजगार छिन गया है। लोगों के हाथों से रोटी छिन जाना, एक अपराध ही है। साथ ही उन्हें पुलिस की बर्बरता का शिकार भी होना पड़ा है।

लाखों लोगों के हाथों से आजीविका और काम छिन जाने से उनके जीवन पर भुखमरी का संकट मण्डरा रहा है। भूख और कुपोषण की संरचना भी औद्योगिक खेती और वैश्विक खाद्य प्रणाली के ही उत्पादन हैं। औद्योगिक खेती का दुष्चक्र छोटे खेतों और छोटे किसानों को नष्ट करने पर लगा हुआ है। छोटे किसान मात्र 25

दुनिया में भूख से पीड़ित लोगों की सबसे ज्यादा संख्या कहीं है, तो वह भारत में है। 2019 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत 102वें स्थान पर है।

प्रतिशत जमीन का उपयोग करते हुए 70 प्रतिशत भोजन का उत्पादन करते हैं। भारतीय भोजन प्रणाली छोटे खेतों पर आधारित है। क्योंकि, छोटे खेत जैव विविधता आधारित, किसानों के गहन ज्ञान और समझदारी होते हैं, इस लिए वे अधिक उत्पादन देते हैं।

छद्म या झूठी उत्पादकता भी जमीन हड़पने का एक नाजायज साधन ही है। 1991 के स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट के बाद से छोटे किसानों की जमीनों को ठेका खेती या भूमि अधिग्रहण एक्ट में बदलाव के जरिए हड़पने की कोशिश की गई। बीज स्वराज और भू स्वराज, अन्न स्वराज की नींव हैं। भारत तभी आत्मनिर्भर होगा जब किसान आत्मनिर्भर होगा। और किसान तभी आत्मनिर्भर होगा जब कोई भूखा नहीं रहेगा, जब भू स्वराज, बीज स्वराज, ज्ञान स्वराज और आर्थिक सम्प्रभुता का संरक्षण होगा।

भारत में कुपोषण के संकट की तरह कृषि संकट भी गहराता रहा है। अब हमारे 4 लाख किसान भाइयों ने आत्महत्या कर दी है। दुनिया में भूख से पीड़ित लोगों की सबसे ज्यादा संख्या कहीं है, तो वह भारत में है। 2019 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत 102वें स्थान पर है।

कार्पोरेट/निगम तथा अरबपति लोग अब उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल खेती और ***'किसानों के बिना खेती'*** की बात कर रहे हैं। इस कारण से भूमि का क्षरण, भूख का संकट, काम का संकट, ज्ञान का संकट, बाहरी आदानों जैसे बीज, खाद, कीटनाशकों, तेल, मशीनरी पर निर्भरता बढ़ेगी। औद्योगिक खेती में बड़ी चतुराई से जीवाश्म ईंधन और जहरीले रसायनों के अंधाधुंध उपयोग के आंकड़ों को छुपाती है। ऐसी खेती 50 प्रतिशत ग्रीन–हाउस गैसों के उत्सर्जन का योगदान देती है। ये गैसे जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। ये संकट जीव प्रजातियों की विलुप्ति के कागार पर धकेलते हैं।

एग्रीबिजनेस और औद्योगिक खाद्य प्रणाली तथा स्वास्थ्य आपातकालः विज्ञान बताता है कि कोरानो, एचआईवी, ईबोला, इनफ्लूंजा, एमईआरएस जैसी बीमारियां पशुओं से मनुष्यों में आई है। ऐसा सघन औद्योगिक खेती के द्वारा पारिस्थितिक तंत्र, असीमित और बेलगाम व्यापार मॉडल अपनाने के कारण हुआ है। उदाहरण– अमेजन को जीएम सोया और इंडोनेशिया के वर्षा वनों को ताड़ के तेल के लिए सफाया करना। ज्ञात हो कि 90 प्रतिशत जीएम सोया जैव ईंधन और जानवरों के भोजन के उपयोग में लाया जाता है। ये उत्पादक हमारी खेती के हिस्सा नहीं हैं। बल्कि, खेती तो जमीन की देखभाल करना है। भोजन से हमें पोषण मिलता है। औद्योगिक आधारित पौधों और जानवरों की एकल खेती से बीमारियां ही फैलती हैं, नई तरह की महामारी उत्पन्न होती है, असाध्य बीमारियों का प्रसार होता है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि कोविड–19 की वजह से होने वाली 70 प्रतिशत मौतें ऐसी थीं, जिसमें मृतक पहले से ही पर्यावरण और खानपान जनित बीमारियों से संक्रमित थे।

कोविद–19 की भरपाई के लिएः धरती पर उतरो और घर को लौटोः पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था दोनों की जड़े घर से निकलती हैं। पारिस्थितिकी के ज्ञान के आधार पर घर की अर्थव्यवस्था की देखभाल हो सकती है। पारिस्थितिकी का व्यवहारिक ज्ञान प्रकृति और सामाजिक दुनिया में संतुलन कायम करती है। संसाधनों के अनियंत्रित दोहन जीव प्रजातियों को विलुप्ति के कागार पर खड़ी करती हैं। इससे जलवायु आपदाओं को गति मिलती है और पारिस्थितिक–तंत्र ध्वस्त हो जाता है।

इसी तरह से अर्थव्यवस्था समाज का हिस्सा है। अर्थव्यवस्था को लोकतांत्रिक नियंत्रण से बाहर और समाज की पहुंच से ऊपर रखा गया है, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, देख–रेख के मूल्य, सद्भावनाओं के मूल्य को दरकिनार करते हुए शोषणकारी वैश्विक बाजार केवल अपने लाभ की बात करता है। आज प्रतिस्प्रर्द्धा ने सहयोग की भावना के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी है। अधिकाधिक लोगों को आजीविका और आवश्यकता के संदर्भ में अर्थव्यवस्था से बाहर रखा गया है।

सभी को मिलकर जैविक खेती करने, लघु उद्योग आधारित स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और बेरोजगार लोगों को काम देने का अवसर आ चुका है। हस्त–निर्मित वस्तुएं जीवाश्म ईंधनों से मुक्त हैं। जहर मुक्त हैं। इन्हें बढ़ावा देने का समय आ गया है।

(क्रमशः जारी ...)

किसान ही बनायेगा भारत को आत्मनिर्भर

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के भगीरथ प्रयास शुरु कर दिये है। प्राचीनकाल से 'सोने की चिड़िया' कहलाने वाले भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि व किसान क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता चला आ रहा है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के इस प्रयास में कोराना, चीन, पाकिस्तान इत्यादि ने बाधा खड़ी की है। परंतु फिर भी त्याग, संकल्प, समर्पण तथा लगन भारत को निकट भविष्य में आत्मनिर्भर बनने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकेगी। आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार ने किसानों व कृषि से संबंधित कई अधिनियमों में संशोधन किया है। अधिनियमों में यह सुधार ही आत्मनिर्भर भारत की नींव होंगे। राजनीतिक स्तर पर भी इसका विरोध नहीं होगा तथा राज्यों में भी सुधारों की शुरुआत हो सकेगी।

भारत के इतिहास में अर्थव्यवस्था व राजनीतिक ताने–बाने का आधार कृषि तथा किसान ही रहा है। एक बार यदि कृषि सुधारों का रास्ता तैयार हो गया तो किसानों के पैरों में पड़ी जंजीर खुल जायेगी। बजटीय प्रावधान 61 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उधर मनरेगा में भी एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है। अब जल संसाधन भी मनरेगा में शामिल होगा।

कृषि क्षेत्र में आठ क्षेत्र– पशुपालन, ड़ेयरी, सुक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, कृषि क्षेत्र का ढ़ाचांगत विकास, जड़ी बूटी, मधुमक्खी पालन, मत्स्य तथा ऑपरेशन ग्रीन व जल संसाधन के क्षेत्रों पर अधिक महत्व दिया जायेगा। कृषि सुधार के लिए कृषि मूल्य उपज और गुणवत्ता के लिए कानून की अवधारणा पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी की गई थी, परंतु राज्यों पर कृषि का दायित्व होने के कारण इस कानून की आवश्यकता को कोई बल नहीं मिल सका था। अब कांट्रेक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया गया है। जिसके लागू हो जाने के बाद

भारत में कृषि व किसानों की स्थिति यदि सुधर जाती है तो भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में देर नहीं लगेगी, जिससे सर्वागींण विकास का वातावरण बन सकेगा।

– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

किसान को लाभ होगा, क्योंकि यह मांग आधारित खेती पूर्व निर्धारित मूल्य पर किया जायेगा। जिससे कृषि में जोखिम भी कम हो जायेगा। किसानों के लिए मंड़ी एक्ट अर्थात एपीएमसी के प्रावधान कठिनाई का कारण थे। इसमें संशोधन से राज्यों के हित टकराते है। राजनीति भी प्रमुख होती है। राजनीतिक दलों का उपस्थिति स्थानीय कमेटियों में भी होती है। जिससे कृषि उपज के व्यापार में मध्यस्थों का एकाधिकार बना हुआ है।

केंद्र सरकार ने वर्ष 1999 में मॉड़ल एपीएमपी एक्ट बनाकर राज्यों को भेजा था, परंतु राज्य इसके प्रति उदासीन ही बने रहे। वर्ष 2017 में भी पुनः संशोधन करके मॉड़ल एक्ट को राज्यों के पास भेजा गया था, परंतु राज्यों की उदासीनता नहीं टूटी। अब सरकार ने केंद्रीय एपीएमसी एक्ट की घोषणा की गई है। इसी प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के पुराने पड़े प्रावधानों के उन्मूलन के लिए गत सरकारों ने प्रयास नहीं किये। वर्तमान में खाद्यान्न के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन चुका है व खाद्यान्न का निर्यात भी किया जा रहा है। इस अधिनियम की प्रतिबंधित सूची में चावल, गेहूं, दलहन, और तिलहन, आलू व प्याज भी है। इन जिंसों में खाद्य प्रोसेसिंग सेक्टर, निर्यातकों और बड़े उपभोक्ताओं को मुश्किल पेश आती थी। जिसका प्रभाव कृषकों पर भी पड़ता है। अब सरकार ने इन जिंसों को बाहर करके सुधार का एक बड़ा फैसला लिया है।

सभी पीएम–किसान लाभार्थियों को केसीसी के दायरे में लाने की योजना के अंतर्गत वर्ष में 2.5 किसानों को दो लाख करोड़ रुपये के ऋण देने की घोषणा की गई है। अगले सीजन की किश्तें भी नौ करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में जमा करा दी गयी है। मछुआरों के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे 77 लाख टन मत्स्य उत्पादन और अधिक हो सकेगा। विभिन्न योजनाओं में 55 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया जायेगा। सरकार कृषि व संबद्ध क्षेत्रों की लॉजिस्टिक, भंड़ारण, कोल्ड़ चेन, प्रसंस्करण, निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्टर फंड़ के लिए 15 हजार करोड़ रुपये तथा हर्बल कल्टिवेशन के लिए 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके आलावा पशुओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खुरपका तथा मूंहपका बीमारी की रोकथाम व ईलाज के लिए 13,334 करोड़ रुपये का प्रावधान है। कृषि के ढ़ांचागत सुविधाओं के विकास पर एक लाख करोड़ व्यय किये जायेंगे। माइक्रो फूड़ इंटरप्राइजेज को 10 हजार करोड़ रुपये की योजना तैयार की गई है।

कोरोना वायरस से विकसित महामारी कोविड़–19 ने देश की अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों को प्राभावित किया है। इसका प्रभाव कब तक रहेगा, यह अभी भी नहीं कहा जा सकता है। इससे मुकाबला करने के लिए किसानों को मजबूत सहारा देते हुए सभी देशवासियों को साहस का परिचय देते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने के सभी कदमों को मजबूती देनी पड़ेगी। प्रत्येक कीमत पर आर्थिक गतिविधियों को बिना किसी राजनीति सोच समझकर करना पड़ेगा। यह सर्वविदित है कि जिसने साहस के साथ कदम बढ़ाया उसे चूमा भी गया है। देश में ऐसा वातावरण तैयार करना प्रत्येक देशवासी का कर्त्तव्य है कि फिर ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें तात्कालिक रुप से सबकी भूख की परवाह करते हुए किसानों को पैरों पर खड़ा किया जा सके। बैशाखी नहीं सहारे का हाथ देना होगा। भारत में कृषि व किसानों की स्थिति यदि सुधर जाती है तो भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में देर नहीं लगेगी, जिससे सर्वागींण विकास का वातावरण बन सकेगा। ❑❑

डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर 251001 (उ.प्र.), के वाणिज्य संकाय के संकायाध्यक्ष व ऐसोसियेट प्रोफेसर के पद से व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त हैं तथा स्वतंत्र लेखक व टिप्पणीकार है।

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

मुक्त व्यापार नहीं उबारेगा हमें

पूर्वी एशिया के देशों इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलिपीन्स, म्यामार, ब्रुयेनी, कम्बोडिया और लाओस ने आपस में एक मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है, जिसे आसियान नाम से जाना जाता है। समझौते के अंतर्गत इन देशों के बीच माल लगभग शून्य आयात कर पर आ–जा सकता है। आसियान के देशों ने वर्ष 2010 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। उस समय इनके चीन को निर्यात अधिक और आयात कम थे। शुद्ध व्यापार इनके पक्ष में 53 अरब डॉलर प्रतिवर्ष का था। चीन के साथ समझौता करने के बाद यह परिस्थिति बदल गई। वर्ष 2016 में इनके निर्यात कम और आयात अधिक हो गये। इन्हें 54 अरब डॉलर का घाटा लगा। जाहिर है कि चीन को आसियान में सम्मिलित करने से इन देशों को भारी घाटा हुआ है।

प्रश्न है कि यह मुक्त व्यापार घाटा हानिप्रद क्यों हुआ? अर्थशास्त्र का सिद्धांत कहता है कि मुक्त व्यापार से दोनों देशों को लाभ होता है। जो देश जिस माल को कुशलतापूर्वक उत्पादन कर सकता है, यानि अच्छी गुणवत्ता के माल का सस्ता उत्पादन कर सकता है, वह उस माल का उत्पादन एवं निर्यात करेगा और सभी देश जिस माल का कुशल उत्पादन नहीं कर सकते हैं, उसका वे आयात करेंगे। जैसे भारत की दवाएं बनाने में कुशलता है, जबकि बिजली के बल्ब बनाने में हमारा खर्च ज्यादा आता है। ऐसे में मुक्त व्यापार का सिद्धांत कहता है कि भारत को दवाओं का निर्यात करना चाहिए और चीन से बल्बों का आयात करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों देश को लाभ होगा। भारत के उपभोक्ता को चीन में बने सस्ते बल्ब मिल जायेंगे और चीन के उपभोक्ता को भारत में बनी सस्ती दवा। भारत में दवा बनाने में रोजगार उत्पन्न होंगे जबकि चीन में बल्ब बनाने में। इस प्रकार मुक्त व्यापार दोनों ही देशों के लिए लाभप्रद सार्थक हो जायेगा।

अपने देश की प्रशासनिक व्यवस्था तो हमें ही सुधारनी होगी तभी हम विश्व बाजार में खड़े रह सकेंगे। 1991 के संकट ने हमें विश्व के लिए खुलवाया था। 2020 के संकट से यदि हम अपने को बंद कर लेते हैं तो जीवित रहेंगे।

– **डॉ. भरत झुनझुनवाला**

लेकिन ऊपर बताया गया प्रत्यक्ष अनुभव बताता है कि आसियान देशों ने जब चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया तो उनका घाटा बढ़ गया। इसका कारण यह है कि मुक्त व्यापार में सब देशों के बीच "नीचे की तरफ दौड़" लागू हो जाती है। जो देश अपने श्रमिक एवं पर्यावरण के प्रति सबसे घटिया रुख अपनाएगा वही रुख सभी देशों को अपनाना पड़ेगा। जैसे यदि चीन में श्रम कानून ढीले हैं; फलस्वरूप चीन में उत्पादन लागत चीन में कम आती है। इस परिस्थिति में यदि चीन के साथ आसियान ने मुक्त व्यापार का समझौता किया, तो आसियान को भी अपने श्रम कानून नरम बनाने होंगे, अन्यथा आसियान देशों में माल के उत्पादन लागत अधिक आएगी। श्रम कानून नर्म होने के कारण चीन का माल सस्ता पड़ेगा; और आसियान देश बाजार में पिट जायेंगे। अथवा मान लीजिये चीन में पर्यावरण की हानि की छूट है। उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण करने पर रोक नहीं है अथवा प्रदूषित पानी को नदियों में डालने पर रोक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में चीन में उत्पादन लागत कम आएगी और चीन का माल सस्ता पड़ेगा। उसके सामने टिकने के लिए आसियान देशों को भी अपने पर्यावरण को नष्ट होने देना पड़ेगा अन्यथा उनका माल महंगा पड़ेगा। तीसरा कारण प्रशासनिक व्यवस्था का है।

चीन की प्रशासनिक व्यवस्था कुशल है, उद्यमी को सुविधा है और उसकी उत्पादन लागत कम आती है। आसियान देशों में यदि प्रशासन सुस्त है तो उनकी उत्पादन लागत ज्यादा आएगी। इन तीनों कारणों से– यानि श्रम और पर्यावरण का घटिया होने और प्रशासन का चुस्त होने के कारण चीन का माल विश्व बाजार में सस्ता पड़ रहा है। ऐसे में अन्य देशों के सामने विकल्प है कि या तो इसी के समकक्ष अपनी व्यवस्था बनायें या फिर चीन से पिटें या चीन से व्यापारिक दूरी बनाये रखें।

दूसरी समस्या यह है कि भारत की महारत सेवा क्षेत्र में है। जैसे– सॉफ्टवेयर, सिनेमा, संगीत, अनुवाद, डेटा अनाल्सिस, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, ऑनलाइन टिटोरियल इत्यादि में। लेकिन आसियान समेत विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुराष्ट्रीय समझौतों में सेवा क्षेत्रों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। मुख्यतः मुक्त व्यापार क्षेत्र में केवल भौतिक माल के आवागमन की व्यवस्था होती है। लेकिन मन्युफैक्चरिंग में हमारी परिस्थिति कमजोर है जिसके कारण मुक्त व्यापार समझौता करके हम मन्युफैक्चरिंग में पिटते हैं चूँकि इसमें हम कमजोर है; और सेवा क्षेत्र का लाभ नहीं उठा पाते। क्योंकि यह मुक्त व्यापार समझौतों के बाहर रहता है। इसलिए हमारे लिए मुक्त व्यापार समझौते अप्रासंगिक हो जाते हैं।

तीसरी समस्या है कि मुक्त व्यापार समझौतों के अंतर्गत पूंजी को सम्पूर्ण विश्व में विचरण करने की छूट मिल जाती है। यदि भारत में श्रम और पर्यावरण कानून कठोर और प्रशासन सुस्त है तो वह अपनी पूंजी को चीन ले जाकर चीन में माल का उत्पादन कर सकता है और वहां से भारत को स्वयं को माल का निर्यात कर सकता है। इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए मुक्त व्यापार निश्चित रूप से लाभप्रद होता है, क्योंकि वे अपनी पूंजी को उस देश में निवेश कर सकते हैं जहाँ पर उन्हें अधिकतम सुविधाएँ मिलें। लेकिन हर देश के नागरिकों के लिए पूंजी का यह विचरण लाभप्रद होना जरूरी नहीं है। अपने देश में चूँकि प्रशासनिक व्यवस्था लचर है इसलिए मुक्त व्यापार अपनाने से हमारी पूंजी शीघ्र ही बाहर चली जाएगी और हमारे नागरिकों को रोजगार नहीं मिलेगा, जैसा कि हम लगातार होता देख रहे हैं। यदि हम मुक्त व्यापार से बाहर रहते हैं तो लचर प्रशासनिक व्यवस्था के बावजूद उद्यमी को भारतीय बाजार में माल बेचने के लिए भारत में ही उत्पादन करना पड़ेगा और तदानुसार भारत में रोजगार भी मिलेंगे। इसलिए मुक्त व्यापार की थ्योरी तीन बिंदुओं पर असफल हो जाती है। पहला यह कि मुक्त व्यापार उस देश के लिए लाभप्रद होता है जिसके श्रम एवं पर्यावरण कानून लचर हों और प्रशासन चुस्त हो। भारत का प्रशासन लचर है इसलिए भारत इसमें मार खाता है। दूसरा यह कि भारत सेवा क्षेत्र में कुशल है जो कि इन समझौतों से बाहर रहता है, और तीसरा कि इस परिस्थिति में मुक्त व्यापार समझौते से हमारी पूंजी का पलायन होता है और हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ती है।

इस समय कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए भारत के सामने दो रास्ते खुले हैं। एक रास्ता यह है कि हम मुक्त व्यापार को और गहराई से अपनाएं और आशा करें कि इससे हमें लाभ होगा। दूसरा रास्ता है कि हम मुक्त व्यापार से पीछे हटें और उससे भी हमें लाभ हो सकता है। मेरा मानना है कि जब तक हम अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करते हैं तब तक हम मुक्त व्यापार में नहीं जीत पाएंगे। इसलिए सरकार को पहले देश के प्रशासन को सही करना चाहिए और उसके बाद ही मुक्त व्यापार पर विचार करना चाहिए। श्रम और पर्यावरण कानून का विषय मेरे हिसाब से द्वितीय स्तर का है और इस पर दूसरे देशों पर इन्हें सुधार करने के लिए दबाव डाला जा सकता है लेकिन अपने देश की प्रशासनिक व्यवस्था तो हमें ही सुधारनी होगी तभी हम विश्व बाजार में खड़े रह सकेंगे। 1991 के संकट ने हमें विश्व के लिए खुलवाया था। 2020 के संकट से यदि हम अपने को बंद कर लेते हैं तो जीवित रहेंगे।❑❑

संकट-काल में जीवनरेखा बनी कृषि

अतीत में उठाए गए कदमों को गिनाने के बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कांफ्रेंस की अपनी श्रृंखला में ग्यारह विशिष्ट उपाय किए हैं; इसके अलावा उन्होंने कोविड-19 के लिए जारी 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के हिस्से के रूप में किसानों की मदद करने के लिए भी दो उपायों की घोषणा की थी। लेकिन इसमें संकट में फंसे किसानों के हाथों में सीधे नकद हस्तांतरण प्रदान करने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं था। हालांकि इनमें से अधिकांश उपाय पहले से ही बजट प्रस्तावों में शामिल हैं।

सीतारमण ने कृषि विपणन को आसान बनाने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत स्टॉक सीमा हटाने के लिए तीन उपायों की भी घोषणा की, यह एक ऐसा कदम है, जो प्रसंस्करण उद्योग और थोक व्यापार में मदद करेगा। असाधारण समय को छोड़कर, जब आपदा आती है या जब खराब होने वाली फसलों की कीमतें सौ फीसदी और अनाज की कीमतें पचास फीसदी अधिक हो जाएं, व्यापारी अब जमाखोरी नहीं कर सकेंगे। किसानों को अपनी उपज बाजार में उपलब्ध कराने के लिए कई विकल्प प्रदान करने वाला एक केंद्रीय कानून और अनुबंध खेती की सुविधा प्रदान करने के लिए कानून शीघ्र ही लाया जाएगा।

फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह समुद्री और अंतर्देशीय (घरेलू) मत्स्यपालन के लिए 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की गई है। इसके अलावा डेयरी इन्फ्रास्ट्रक्चर और अन्य जारी योजनाओं के लिए 15,000 करोड़ रुपये तथा पशुओं के खुरपका तथा मुंहपका बीमारी की रोकथाम के लिए 13,343 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। सभी पशुओ का सौ फीसदी टीकाकरण किया जाएगा, जिसे मई, 2019 में कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। औषधीय पौधों, मधु मक्खीपालन, सूक्ष्म खाद्य

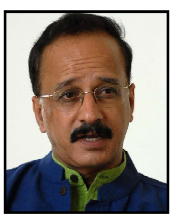

यह महामारी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार करने का अवसर प्रदान करती है। कृषि को पुनर्जीवित करना और खेती को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाना इस अभियान का आधार है।

– देविन्दर शर्मा

उद्यमों में पोषण आहार, स्वास्थ्य और कल्याण आदि के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई है। बेशक ये महत्वपूर्ण उपाय हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं, तथा किसानों, मछुआरों और दुग्ध उत्पादक किसानों की मदद करेंगे, पर ये ऐसे कदम हैं, जो दीर्घकालीन कृषि गतिविधियों में सुधार के लिए सतत प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

मौजूदा संकट के दौर में जब लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां गंभीर रूप से ठप हैं, केवल कृषि ही जीवन–रेखा बनी हुई है। सही मायने में कृषि ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार के रूप में अपनी छवि मजबूत की है। पर रेस्तरां और ढाबों के लगभग 50 दिनों से बंद होने के कारण शहरी मांग घट गई है, जिसका कृषि को भारी खामियाजा उठाना पड़ा है, लेकिन फिर भी इसने आपूर्ति जारी रखी है।

खबरें हैं कि नियमित रूप से आपूर्ति बाधित होने के कारण किसानों को सड़कों पर दूध बहाना पड़ा, मुर्गियों को जिंदा जलाना पड़ा, फूलों के खेत फिर से जोतने पड़े, पशुओं के आगे सब्जियां फेंकनी पड़ीं और सभी फसलों की कीमत बाजार में लगभग न्यूनतम स्तर पर चली गई, क्योंकि आपूर्ति शृंखला नियमित रूप से बाधित हुई। अनुमानों के मुताबिक, सब्जी उत्पादकों को 25,000 करोड़ रुपये, दुग्ध उत्पादकों को 10,000 करोड़ रुपये तथा फूल उत्पादकों, नर्सरी वालों, फल उत्पादकों व मछुआरों को भारी नुकसान के अलावे पॉल्ट्री उद्योग को 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

सभी बाधाओं के बावजूद किसानों ने लगभग 10.6 करोड़ टन गेहूं की कटाई की है, खरीफ फसलों की पहले ही ज्यादा बुआई की है, और आने वाले हफ्तों में वे धान रोपाई के लिए भी तैयार हो रहे हैं। कृषि क्षेत्र पहले से ही

मौजूदा संकट के दौर में जब लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां गंभीर रूप से ठप्प हैं, केवल कृषि ही जीवन-रेखा बनी हुई है।

संकट में है, उम्मीद की जा रही थी कि तत्काल राहत पैकेज आंशिक रूप से उन्हें हुए नुकसान की भरपाई करेगा, और बुवाई के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा। यहां सरकार के लिए संकट में किसानों के साथ खड़े होने और ज्यादा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने का अवसर था। किसानों को तत्काल राहत पैकेज की जरूरत है, और उनके हाथों में अधिक नकदी प्रदान करने से अधिक मांग पैदा करने में भी मदद मिलेगी।

इससे पहले भी, जब वित्त मंत्री ने किसानों और समाज के अन्य सीमांत वर्गों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी, किसानों के लिए एकमात्र प्रतिबद्धता पीएम–किसान योजना के तहत 2,000 रुपये की एक किस्त देना था, जो उनका बकाया ही था। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को तीन किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का प्रत्यक्ष हस्तांतरण मिलता है।

अप्रैल–जून तिमाही की पहली किस्त बकाया थी। दूसरे शब्दों में, किसान अब तक किसी भी प्रत्यक्ष समर्थन से वंचित हैं। मेरा प्रस्ताव है कि पीएम–किसान आवंटन में देरी किए बिना बटाईदार किसानों सहित प्रति किसान 10,000 रुपये का प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण प्रदान करना चाहिए। इसके अलावा, किसानों को गेहूं की कटाई और खरीद के समय जो कठिनाइयां झेलनी पड़ीं, उन्हें देखते हुए उन्हें गेहूं खरीद के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाना चाहिए। यह देखते हुए, कि कई लाख प्रवासी श्रमिक अपने गांवों में लौट आए हैं, कृषि को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि अतिरिक्त कार्यबल को खेती में समायोजित किया जा सके।

यह महामारी प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को साकार करने का अवसर प्रदान करती है। कृषि को पुनर्जीवित करना और खेती को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाना इस अभियान का आधार है। मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन एक स्वागत योग्य कदम है। यह दूसरे देशों से सबक लेने का भी वक्त है। अमेरिका ने किसानों से सीधे सब्जियां, फल और दूध खरीदने तथा उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने के लिए तीन अरब डॉलर की मदद दी है। भारत में खराब होने वाली फसलों के लिए इसी तरह की रणनीति पर काम किया जा सकता है। यह वक्त सरकार द्वारा ऐसे कदम उठाने का है, जिससे किसान लाभान्वित हों। आखिरकार, किसानों ने यह प्रदर्शित किया है कि इस कठिन समय में वे अर्थव्यवस्था की वास्तविक रीढ़ हैं। ❑❑

(लेखक कृषि नीति विशेषज्ञ हैं।)

https://www.amarujala.com/columns/opinion/agriculture-became-a-lifeline-in-crisis/

सुदृढ़ नीतियों के अभाव के कारण

देश के कई हिस्सों में बाढ़ की विभीषिका

गर्मी में देश के जिन भागों में जल का अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हुआ था वहां आज अत्यधिक मात्रा में वर्षा होने से अधिकांश भाग बाढ़ से पीड़ित होकर त्राहि–त्राहि कर रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश गुजरात, महाराष्ट्र एवं आसाम आदि की नदियां जल की अगाध राशि से पूरित होकर तटबंधों को तोड़ती हुई सी आगे बढ़ रही हैं और सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है। नदियों में आई हुई यह बाढ़ न तो अचानक आई है और न ही कल्पना एवं सोच के विपरीत। वर्षा ऋतु में वर्षा की अधिकता होने पर बाढ़ आने की संभावना बनी रहती है किंतु इस वर्ष पर्याप्त मात्रा में वर्षा न होने पर भी छोटी बड़ी समस्त नदियां जल से पूरित होकर अपने तटवर्ती इलाकों को जल से आप्लावित कर रही हैं। शासन एवं व्यवस्था को चाहिए था कि वह वर्षा ऋतु के आने के पूर्व ही बाढ़ की विभीषिका के समाधान हेतु प्रयास करता, पर हर साल की तरह इस बार भी कहानी वही ढाक के तीन पात वाली ही है। इसमें कोई शक नही कि यदि शासन व्यवस्था समय रहते चेत ले तो इस बाढ़ की समस्या से स्थायी तौरपर निजात पाया जा सकता है, किंतु नीति नियंताओं की सोच एवं उनकी विचित्र कार्यप्रणाली के चलते ऐसा कुछ नहीं होता, परिणाम स्वरूप गर्मी में जहां एक और देश को जल की कमी का संकट झेलना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर वर्षा ऋतु में बाढ़ की विभीषिका का सामना करते हुए जन धन हानि का भी सामना करना पड़ता है।

भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण बाढ़ की विभीषिका को लेकर अत्यधिक संवेदनशील है जिसके परिणामस्वरूप देश के लगभग 12.5 प्रतिशत भाग को प्रतिवर्ष बाढ़ का सामना करना पड़ता है।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण बाढ़ की विभीषिका को लेकर अत्यधिक संवेदनशील है जिसके परिणाम स्वरूप देश के लगभग 12.5 प्रतिशत भाग को प्रतिवर्ष बाढ़ का सामना करना पड़ता है। देश में बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश केरल असम बिहार महाराष्ट्र गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा और पंजाब छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं, जिनमें बाढ़ का प्रकोप प्रतिवर्ष देखने को मिलता है। प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश का लगभग 7.33 लॉख हेक्टेयर क्षेत्र जल से डूब जाता है। इसी प्रकार बिहार में 4.26 लाख हेक्टेयर, पंजाब में 3.7 लाख हेक्टेयर, राजस्थान में 3.26 लाख हेक्टेयर, आसाम में 3.15 लाख हैक्टेयर, बंगाल में 2.6 5 लाख हेक्टेयर, उड़ीसा में 1.4 लाख हेक्टेयर और आंध्र प्रदेश में 1.39 लाख हेक्टेयर केरल में 0.87 लाख हेक्टेयर, तमिलनाडु में 0.4 5 लाख हेक्टेयर, त्रिपुरा में 0.33 लाख हेक्टेयर तथा मध्य प्रदेश में 0.2 6 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है। इन राज्यों की ही भांति हिमांचल प्रदेश का 0.23 लाख हेक्टेयर महाराष्ट्र का 0. 23 लाख हैक्टेयर, जम्मू कश्मीर का 0.1 लाख हेक्टेयर, मणिपुर का 0.08 लाख हैक्टेयर, दिल्ली का 0.08 लाख हेक्टेयर, कर्नाटक का 0.02 लाख हेक्टेयर, मेघालय का 0.02 लाख हेक्टेयर, पांडिचेरी का 0.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ प्रतिवर्ष

प्रभावित करती है जिससे कम से कम 13 अरब 40 करोड़ का नुकसान पहुंचता है। बाढ़ के प्रकोप से प्रतिवर्ष लगभग 1600 व्यक्तियों की मौत होती है और 95000 जानवर काल के गाल में समा जाते हैं। यह आंकड़ा वर्ष में होने वाली सामान्य वर्षा का है किंतु जिन वर्षों में वर्षा सामान्य से अधिक होती है उन वर्षों में समस्त राज्यों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी काफी बढ़ जाता है तथा वहां जनधन की अपार हानि होती है।

वर्षा जब प्रतिवर्ष होती है और उसे होना ही है तो उसके प्रभाव से आने वाली संभावित बाढ़ के रोकथाम के लिए पूर्व में ही सार्थक प्रयास क्यों नहीं किए जाते। मानसून आते ही देश के कई हिस्से डूबने लगते हैं। आज असम बिहार गुजरात और महाराष्ट्र के अनेक भागों में बाढ़ जनित आपदा से कोहराम मचा हुआ है, और यह स्थिति तब है जब अभी मानसून का एक माह भी पूरा नहीं हुआ है, मानव की तो बात छोड़िए जानवर भी जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कृषि को तो यह बाढ़ समाप्त ही कर चुकी है, घर में रखा हुआ सामान भी लगभग बर्बाद हो चुका है। यह तो अभी शुरुआत है कुछ दिन बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश व देश की अन्य अनेक नदियां खतरे के निशान से ऊपर पहुंच विकराल स्वरूप ग्रहण कर अपनी विनाशलीला का प्रदर्शन करेंगी। अभी तो गंगा यमुना एवं उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आई ही नहीं। अभी लगभग एक माह पूर्व जिस पानी की एक एक बूंद के लिए देश में मारा मारी, आज वही पानी काल का रूप दिख रहा है। अभी देश के हर क्षेत्र में वर्षा सामान्य ही हुई है कहीं भी अतिवृष्टि नहीं हैं, फिर भी अनेक राज्यों में बाढ़ की समस्या से त्राहि–त्राहि मची हुई है।

वस्तुतः इस स्थिति के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। नदियों के तटवर्ती क्षेत्र में अतिक्रमण कर उनके जल प्रवाह को अत्यंत संकरा कर दिया गया है, इतना ही नहीं अतिक्रमण की प्रवृत्ति ने अनेकानेक नदियों को तो समाप्त ही कर दिया है बस मात्र उनका नाम ही शेष है। अन्य ऋतु में जल की कमी तथा एक एक बूंद के लिए तरसते लोग इन नदियों का स्मरण कराते हैं किंतु वर्षा ऋतु आते ही इन नदियों के माध्यम से बह जाने वाला पानी मार्ग न पाकर पूरे क्षेत्र को जल आप्लावित्त कर देता है जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। रही– सही कसर नदियों की तलहटी में जमा हुई गाद के प्रभाव से उनकी कम होती गहराई पूरा कर देती है। पहले की सामाजिक व्यवस्था में वर्षा जल को नियंत्रित करने के लिए अनेक व्यवस्थाएं की जाती थी। तालाब, पोखर, झील, कुंआ, बावड़ी इत्यादि का निर्माण कराया जाता था, जिससे वर्षा का जल पहले जल स्रोतों में इकट्ठा होता था तथा अवशोषित होकर भूगर्भ में पहुंचता था, उसके बाद जो जल बचता था वह वह कर नदियों में पहुंचता था। किंतु अब जल के इन केंद्रों के न रहने के कारण बरसात होते ही सीधे नदियों में पहुंचता है, जिससे सामान्य वर्षा में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।ऐसे में बाढ़ की विकराल स्थिति पर नियंत्रण के लिए हमें अपनी सोच तथा जल प्रबंधन के ताने–बाने को दुरुस्त कर उसे नए सिरे से गठित करना होगा, तभी नदियां हमारे लिए जीवनदायिनी बनकर प्रवाहित होगी और काल का स्वरूप ग्रहण नहीं करेंगी।

नदियों में तटबंध एवं बांध बनाने की असीमित योजनायें, तटवर्ती क्षेत्रों में अनवरत बढ़ रही आवासीय गतिविधियों तथा खनिज पदार्थों के लिए नदियों के गर्भ के अधाधुंध दोहन से उनका प्रवाह मार्ग बाधित हो जाता है। आज विकास के नाम पर नदी नालों पर छोटे बड़े बांध बनाने तथा छोटी–छोटी नदियों में भी चेक डैम बनाकर उनके पानी को रोकने का प्रयास किया जाता है, जिसके दुष्प्रभाव पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं। अबाध शहरीकरण की प्रक्रिया वनविनाश और खनन को बढ़ावा देती हुई कंक्रीट केजंगल उगाने में लगी हुई है। निरंतर नए–नए कंक्रीट के जंगल उग रहे हैं तथा वृक्ष एवं वन गायब हो रहे हैं, जिससे धरती की पानी सोखने की क्षमता कम हो रही है और पानी के बहाव की गति काफी बढ़ रही है जिससे वर्षा का जल प्रबल वेग से बहकर व्यर्थ में बह जाने के लिए नदियों में चला जाता है। वस्तुत इसके लिए हम ही उत्तरदायी और हम ही इससे पीड़ित हैं और हमें ही इससे बचाव के रास्ते खोजने हैं। बाढ़ से नदियों की गाद तटवर्ती क्षेत्रों में फैलकर खेतों में बिछ जाती है तब वह प्राकृतिक खाद का कार्य कर खेतों में सोना उगलती है। वही गाद जब जल की धारा में निरंतर जमा होती रहती है तब वह नदी के प्रवाह की गहराई को बाधित कर देती है तो जल की अधिकता होने पर नदी का पानी तटवर्ती क्षेत्रों में फैलता है और विनाशकारी बाढ़ आती है। नदियों के जल प्रवाह क्षेत्र की समस्या को लेकर एक मात्र गंगा नदी के संदर्भ में अध्ययन कार्य हुआ है। गंगा नदी देश की सबसे बड़ी नदी है जिसका बेसिन सबसे बड़ा बेसिन है और देश की 45 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर है, लेकिन गाद की समस्या से गंगा भी संत्रस्त है।भारत सरकार के जल संरक्षण नदी विकास और गंगा मंत्रालय के अंतर्गत गठित एक कमेटी ने अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी में अतिक्रमण और जमा होने वाली गाद का अध्ययन कर उत्तराखंड के भीमगोड़ा से लेकर पश्चिम बंगाल के फरक्का बांध तक गंगा को गाद से मुक्त करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 41.3 करोड़

टन गाद जमा होती है। हिमालय से निकलकर गंगा में मिलने वाली अनेक छोटी नदियां अपने साथ 90 प्रतिशत गाद लेकर आती हैं। पश्चिम बंगाल में फरक्का बांध के निर्माण के बाद से गंगा में गाद जमा होने की समस्या बढ़ गई है, इससे बिहार में बाढ़ का स्तर बढ़ गया है। फरक्का बांध ने कोलकाता बंदरगाह में गाद कम करने में कोई भूमिका नहीं निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप गाद की अधिकता के कारण पानी की गहराई कम होने से हिलसा जैसी देसी मछलियों की संख्या काफी कम हो गई है, इससे क्षेत्र का पर्यावरणीय संतुलन भी बिगड़ रहा है। इससे निजात पाने के लिए आवश्यक है गंगा के बेसिन में जमा गाद के स्तर को कम किया जाए तथा उसे प्रतिवर्ष जमा होने से रोका जाए।बाढ़ नियंत्रण के लिए वर्षा जल का संरक्षण एवं उसका प्रबंधन अनिवार्य आवश्यकता है।

देश की सबसे बड़ी नदी गंगा भी इससे अछूती नहीं है, अरबों रुपए खर्च कर देने के बाद भी अभी तक उसे निर्मल नहीं बनाया जा सका है। वस्तुतः स्थान स्थान पर तालाब पोखर झील बावड़ी कुआं आदि बनाकर वर्षा के जल को प्रकृति एवं जीवन जीवन की रक्षा के लिए संरक्षित किया जा सकता है जैसा कि पूर्व में हमारे पूर्वजों द्वारा किया जाता रहा है प्राकृतिक तथा मानव निर्मित केंद्रों में जल इकट्ठा होकर धीरे धीरे अवशोषित हुआ होता हुआ भूगर्भ जल स्तर को काफी बढ़ा देता है जिससे जल की समस्या का समाधान भी हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल को नदियों तक पहुंचकर व्यर्थ में ना बहने दिया जाए और उसे येन केन प्रकारेण संरक्षित कर भूगर्भ में पहुंचाने के लिए प्रयास किया जाए, जिसके लिए भूजल एक्वीफर्स प्राकृतिक रूप से मिले वरदान हैं। वनाच्छादित भूमि प्राकृतिक रूप से जल का संग्रहण कर भूगर्भ के जल स्तर को ऊपर बनाए रखने में सर्वाधिक योगदान देती है जिसे दृष्टिगत रखते हुए जल संरक्षण हेतु वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता है।

वस्तुतः जल संरक्षण और उसका कुशल प्रबंधन ही बाढ़ पर नियंत्रण प्राप्त करने का एक मात्र साधन है जिसके लिए सर्वप्रथम वनों के विनाश पर रोक, शहरीकरण के नाम पर मनमाने ढंग से उग रहे कंकरीट के जंगलों पर प्रतिबंध, नदियों के गर्भ से खनिजों का आधा धुंध दोहन कर उनके प्राकृतिक प्रवाह मार्ग को बाधित करने से रोककर उन्हें अपनी गति से प्रवाहित होने देना जैसे कार्य कर, सफल जल प्रबंधन करते हुए जल की विभीषिका को रोका जा सकता है। अन्यथा वर्षा का असीमित जल अनियंत्रित रूप से नदियों में पहुंच कर बाढ़ की विभीषिका को ही मूर्त रूप देगा जो प्रतिवर्ष मानव सभ्यता और संस्कृति के समक्ष चुनौती के रूप में उपस्थित रहेगी। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें : **http:// swadeshionline.in/**

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	*वार्षिक*	*आजीवन*
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC: BKID-0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

प्रवासी श्रमिकों के लौटने से खुली पोल

दीर्घकालीन नीति से ही बदलेगा बुंदेखण्ड

वैश्विक महामारी कोविड–19 के चलते महानगरों से प्रवासी श्रमिक अपने घरों को मजबूरी में लौटे हैं। ये श्रमिक किस प्रकार और किन–किन माध्यमों से कितनी विषम परिस्थितियों में लौटे हैं, ये सर्वविदित है। तथ्य बताते हैं कि जो श्रमिक बुंदेखण्ड के इन 16–17 जिलों (जिनमें मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के जिले सम्मिलित है) से रेल के माध्यम से महानगरों की और गये थे, उनकी संख्या लगभग 28 लाख थी। बसों के माध्यम से कितने मजदूर महानगरों में रोजगार के लिये गये, इसकी संख्या उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि बुंदेलखण्ड क्षेत्र के प्रत्येक जिले से यह प्रवासी मजदूरों की संख्या एक लाख के ऊपर है।

साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में प्रतिवर्ष 6 करोड़ मजदूर रोजगार के लिये भारतीय गांव से महानगरों की ओर पलायन करते हैं। ये वो आंकड़े हैं जो कहीं न कहीं लिखित रूप में संकलित हैं। इनमें वह आंकड़े उपलब्ध नहीं है जो असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक काम करते है, उनका लेखा–जोखा इसमें नहीं है। गांव से शहरों की ओर पलायन का यह आंकड़ा 8–10 करोड़ के लगभग वर्तमान समय में होना चाहिए। क्योंकि यह 2020 का साल है, जनगणना के 10 वर्ष पहले की।

तथ्य बताते हैं कि बुंदेलखण्ड के छतरपुर जिले में ही अकेले लगभग 75000 श्रमिक इस लॉकडाउन पीरियड में अपने गांव लौटे हैं, ये वो तथ्य है जो कहीं न कहीं दर्ज किये गये हैं। इनमें वो संख्या नहीं है जो अपने साधनों से या पैदल या फिर अभी महानगरों से अपने घरों को लौट ही नहीं पाये।

इस रिवर्स माइग्रेसन के कारण कोविड–19 का संक्रमण बुंदेलखण्ड के गांवों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। यद्यपि भारत सरकार, राज्य सरकारें एवं जिला सरकार का पूरा ध्यान इन लौटे प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं रोजगार देने पर है।

बुंदेलखण्ड के छतरपुर जिले में ही अकेले लगभग 75000 श्रमिक इस लॉकडाउन पीरियड में अपने गांव लौटे हैं, ये वो तथ्य है जो कहीं न कहीं दर्ज किये गये हैं। इनमें वो संख्या नहीं है जो अपने साधनों से या पैदल या फिर अभी महानगरों से अपने घरों को लौट ही नहीं पाये।

– डॉ. जयप्रकाश मिश्र

परंतु प्रश्न ये है कि आखिर सरकार इन श्रमिकों की व्यवस्था कब तक और कहां तक करें? इन मजदूरों के हुनर के प्रयोग के लिये अल्पकालीन योजनाओं के साथ दीर्घकालीन योजनायें बनाने की आवश्यकता है। अल्पकालीन योजनाओं में सरकार से जो बन पड़ रहा है, वह कर रही है। उदाहरण के लिये मनरेगा में जो न्यूनतम मजदूरी दर 182 रुपये प्रतिदिवस थी उसे मार्च 2020 बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया था। रोजगार चाहने वाले श्रमिक को कम से कम 100 दिवस का रोजगार तो वर्ष भर में मिलेगा। मेरा मानना है कि सरकार को मनरेगा में कार्यदिवस 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस करना चाहिए। शासन द्वारा अनेक तरह के निर्माण कार्य गांव स्तर पर संचालित रहते हैं, जैसे– सड़के, स्कूल, अस्तपताल आदि के कार्य उनमें इन मजदूरों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

इसी तरह बुंदेलखण्ड के इन जिलों में लगभग सात हजार तालाब हैं। इन तालाबों के रख–रखाब, गहरीकरण, उनके किनारों आदि की मरम्मत 'श्रम प्रधान तकनीकि' के माध्यम से हो, जिससे श्रमिकों को गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। 'पूंजी प्रधान तकनीकी' का उपयोग (जिसमें मशीनें आदि आती हैं) के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाये। क्योंकि अभी जो संकटका समय है उसमें हम सब की भावना 'लाभ केन्द्रित' न होकर 'सेवा केन्द्रित' होना चाहिए। तभी इन श्रमिकों के साथ हम न्याय कर पायेंगे। इसी तरह इन श्रमिकों के कौशल (हुनर) के आधार पर उन्हें गांव में ही छोटे–छोटे लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिये सरकार की मदद से स्थापित किये जाना तत्काल की आवश्यकता है। इसके लिये माननीय प्रधानमंत्री जी ने राहत पैकेज की घोषणा की है।

ये सब इन श्रमिकों को तत्काल रोजगार देने के अल्पकालीन उपाय है। परंतु हमारा चिंतन अब दीर्घकालीन नीतियां बनाकर स्थाई रोजगार देने के लिये स्थानीय संशाधनों पर केन्द्रित किया जाना चाहिये।

दीर्घकालीन नीति बनाने के लिये बुंदेलखण्ड के जिलों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों पर हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा। बुंदेलखण्ड की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और 70 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी जीवकोपार्जन के लिये कृषि पर ही निर्भर है। अतः नदी जोड़ो अभियान वेतवा–केन लिंक परियोजना का शुभारम्भ किया जाना वर्तमान की आवश्यकता है। इन दो बड़ी नदियों के जुड़ाव से जहां 200 वर्ग किमी. के बुंदेलखण्ड के क्षेत्र में नहरों के माध्यम से सिंचाई होने लगेगी। वहीं जिस वर्ष बारिश कम होती है, उस वर्ष वर्षा जल से सूखे की स्थिति में बुंदेलखण्ड चंदेल कालीन तालाबों में नहरों से पानी डालने की योजना भी फलीभूत होगी। परिणामस्वरूप अभी बुंदेलखण्ड का जो किसान मात्र रवि की फसल पर ही, अपना वर्षभर का गुजारा करता है। उसे पानी की उपलब्धता के कारण दो या तीन फसलें उत्पादित करने का अवसर मिलेगा। साथ ही इन परियोजनाओं में यहाँ के स्थानीय मजदूरों को काम मिल जायेगा। जिससे कुछ हद तक ये बाहर से लौटे श्रमिक रोजगार में लग सकेंगे।

इसी तरह एक तथ्य और दीर्घकालीन नीति के लिये बुंदेलखण्ड की परियोजना के लिये आवश्यक हैं। बुंदेलखण्ड के छतरपुर जिले का भौगोलिक क्षेत्र 8400 वर्ग किमी. से अधिक है। जिसमें 3400 वर्ग किमी. में लगभग ग्रेनाईट्स पत्थर के भंडार हैं। अर्थात् कुल भौगोलिक क्षेत्र के पैंतीस प्रतिशत क्षेत्र में ग्रेनाईट्स के भण्डार हैं पर अभी तक इस क्षेत्र में ग्रेनाईट्स माईन्स का कोई विशाल प्रोजेक्ट स्थापित नहीं किया। अब समय है जब बुंदेलखण्ड के इन प्राकृतिक संसाधनों को दोहन, नीति बनाकर किया जाना चाहिये। ये तो छतरपुर का मैंने आंकड़ा बताया। बुंदेलखण्ड क्षेत्र के सभी जिलों में अनेक तरह के पत्थरों की अधिकता है। आप जानते हैं कि पत्थर तोड़ने की क्रेशर मशीनों के प्रोजेक्ट लीज पर लेकर कुछ प्रभावशाली लोग ही इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं।

यदि सरकार के माध्यम से दीर्घकालीन प्रोजेक्ट बनाकर ग्रेनाईट्स माईन्स की एक विशाल परियोजना बुंदेलखण्ड में स्थापित कर दी जाये। तो यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के साथ–साथ इस क्षेत्र के कुशल और अकुशल श्रमिकों को यहीं रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। कच्चे माल के श्रोत के पास ही स्थापित किये जाने से वहाँ के स्थाई निवासियों को अनेक तरह के रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। कहा जाता है कि जब एक क्षेत्र विशेष में कोई विशाल परियोजना की इकाई स्थापित होती है। तब वहाँ अनेक सहायक उद्योग अपने आप स्थापित होने लगते हैं। और वहाँ के स्थानीय लोगों को उन सहायक उद्योगों एवं उनसे जुड़े लोगों की आवश्कता की पूर्ति हेतु अनेक तरह के व्यवसाय अपने आप प्रारंभ हो जाते हैं। कच्चे माल के श्रोत के पास उद्योग स्थापित करने से उस क्षेत्र विशेष का विकास होगा। बुंदेलखण्ड के ये जिले वैसे भी उद्योगविहीन है।

यदि बुंदेलखण्ड से पलायन रोकने के लिये कोई विचार मंथन हो तो इस मेरे विचार को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। साथ ही हम सब बुद्धिजीवियों, योजनाकारों, समाजसेवियों की यह नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि इस वैश्विक महामारी के संकट में हम अपने परिवार के लिये, समाज के लिये और देश के लिये कितने समर्पित हैं। ❑❑

डॉ. जय प्रकाश मिश्र प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, शास. महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

स्वदेशी वारियर्स पर रिपोर्टः बैठकें और रुझान

सोशल मीडिया पर छाए रहे स्वदेशी योद्धा

स्वदेशी वारियर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों का एक समूह है, जो स्वदेशी के दर्शन में एक मजबूत विश्वास रखता है। योद्धाओं का उद्देश्य टवीटर के जरिए स्वदेशी जागरण मंच के विचारों का समर्थन और विस्तार करना तथा प्राथमिकता के आधार पर मंच द्वारा उठाए जा रहे देशहित के आवश्यक मुद्दों के बारे में नीति निर्माताओं और आम जनता का ध्यान आकर्शित करना है। 13 जुलाई 2020 तक, स्वदेशी योद्धा समूह ने टवीटर पर 7 रुझानों को बढ़ावा दिया है। इस दौरान एसजेएम के केंद्रीय नेतृत्व के साथ योद्धाओं की दो बैठकें आयोजित हो चुकी है।

स्वदेशी वारियर्स की पहली बैठक 21 जून 2020 को शाम 6 बजे से हुई। बैठक का समन्वय पूजा मदान जी और गोविंद त्रिपाठी जी द्वारा किया गया और इसे डॉ. फूलचंद ने संचालित किया। बैठक को श्री कश्मीरी लाल और डॉ. अश्वनी महाजन ने संबोधित किया था। श्री कश्मीरी लाल ने नए सदस्यों का स्वागत किया और उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण में स्वदेशी जागरण मंच की भूमिका के साथ अद्यतन किया। डॉ. अश्वनी महाजन ने उन मुद्दों के बारे में विस्तार से बात की, जिनका सामना देश और दुनिया को करना पड़ रहा है। उन्होनें कहा कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वदेशी आर्थिक नीतियों का पालन करने की आवश्यकता है। सभी प्रतिभागी बैठक को लेकर बहुत उत्साहित थे। बैठक में कुल 28 सदस्य उपस्थित हुए।

स्वदेशी वारियर्स की दूसरी बैठक 5 जुलाई 2020 को शाम 4 बजे से 6.45 बजे तक हुई और इसे पूजा मदान और गोविंद त्रिपाठी द्वारा समन्वित किया गया। बैठक की अध्यक्षता और संचालन डॉ. फूलचंद ने किया। इस बैठक में सभी प्रतिभागियों को बोलने और आपस में बात करने का पर्याप्त समय मिला। बैठक का फोकस एसजेएम और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका को समझना था। दर्शकों को ठेंगडी जी के विचारों से अपडेट किया गया और उनके द्वारा लिखी थर्ड वे नाम की किताब को पढ़ने का सुझाव दिया गया। प्रतिभागियों ने ट्विटर प्रवृत्तियों के लिए पहले से विकसित और आगे विकसित की जाने वाली रणनीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रतिभागियों को अपनी रुचि के क्षेत्र को चुनने औरस्वदेशी दर्शन की चिंताओं के खिलाफ जाते मुद्दों को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बैठक के सभी प्रतिभागियों ने सहमति व्यक्त की कि सभी स्वदेशी योद्धा स्वदेशी को जीएं और स्वदेशी को बढ़ावा दें। बैठक में कुल 20 सदस्य उपस्थिति हुए।

स्वदेशी योद्धा अपनी ताकत बढ़ाने और नए लोगों को बंधुत्व में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस क्रम में योद्धाओं ने सोशल मीडिया पर अपनी धमाकेदार उपस्थिति दर्ज की है। बीती 12 जुलाई को शायं 6 बजे से टवीटर पर बैन–कैंसर–काजिंग–ग्लाईफोसेट ट्रेन्ड होने लगा था, जो लगातार बढता ही रहा। इस प्रवृत्ति को प्राप्त करने वाली सर्वश्रेष्ठ रैंक पूरे भारत में ट्विटर के रुझानों में 29वीं थी। 28 जून 2020 को शाम 5 बजे से चाईना–मुक्त–स्वदेशी–भारत ट्रेंड हुई। इस ट्रेंड में 15500 से अधिक ट्वीट थे और पूरे भारत में ट्विटर के रुझानों में सर्वश्रेष्ठ रैंक 30वीं थी। 10 जून 2020 को शाम 5 बजे से स्वदेशी–डिजिटल–सिगनेचर ट्रेंड हुआ। 7000 से अधिक ट्वीट होने के बावजूद, यह प्रवृत्ति पूरे भारत में ट्विटर के रुझानों में 25वें स्थान पर रही। वोकलफारलोकल–स्वदेशी पर 17 मई 2020 को शाम 5 बजे से प्रदर्शन किया गया था और 12000 से अधिक ट्वीट्स के साथ ट्विटर ट्रेंड्स में इसकी सर्वश्रेष्ठ 15वीं रैंक प्राप्त हुई थी। पोखरण–स्वावलंबन–का–संकल्प पर ट्रेंड 11 मई 2020 को 3.45 बजे से किया गया था, जो इससे अधिक था 15000 ट्वीट्स और ट्विटर ट्रेंड के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 22वीं सर्वश्रेष्ठ रैंक प्राप्त की।

स्वदेशी–सेल्फ–रिलायंस 9 मई 2020 को शाम 5 बजे से किया गया और 7000 से अधिक ट्वीट्स के साथ इसे राष्ट्रीय स्तर पर ट्विटर के रुझानों के बीच 16वीं सर्वश्रेष्ठ रैंक प्राप्त हुई। स्वदेशी वारियर्स समूह की ओर से पहला टवीट–25 अप्रैल 2020 को शाम 6 बजे विषय 'स्वदेशी–संकल्प–दिवस' पर हुआ और यह सफलतापूर्वक चलन में भी रहा। योद्धा अपनी ताकत बढ़ाने और नए लोगों को बंधुत्व में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

❑❑

चीनी ऐप बैन, स्वदेशी जागरण मंच बोला – 'बहुत बढ़िया'

चीन से गलवन में हुए सीमा विवाद के बाद केंद्र सरकार ने ड्रैगन को करारा जवाब दिया है। सरकार ने तेवर तल्ख करते हुए 59 चीनी ऐप को बैन करने का आदेश दिया है। सरकार के इस आदेश के साथ ही लोगों में काफी खुशी है। स्वदेशी जागरण मंच ने इसका स्वागत करते हुए कहा है कि यह मोदी सरकार का बहुत ही बेहतर कदम है।

मंच के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख दीपक शर्मा ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच सरकार के इस कदम का स्वागत करता है। इसके साथ ही उन्होंने देश की जनता का धन्यवाद किया। जनता ने स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत सहयोग का हाथ बढ़ाया है। उसका असर विभिन्न क्षेत्रों पर दिखने लगा। चाहे वह टिकटॉक जैसे ऐप बैन हो या बंदरगाह पर आने वाले चीनी सामान पर टैक्स लगाकर किया जाना हो। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार, समाज और सेना समरस होकर देश के लिए अपने–अपने स्तर पर जुट गई है। यह शुभ संकेत है। इससे भारत जल्द ही अपने पैरों पर खड़ा होगा।

इन ऐप पर लगा प्रतिबंध –1. टिकटॉक, 2. शेयरइट, 3. क्वाई, 4. यूसी ब्रोसर, 5. बैडू मैप, 6. शीइन, 7. क्लास ऑफ किंगस, 8. डीयू बैटरी सेवर, 9. हेलो, 10. लाईकी, 11. यूकम मेकअप, 12. एमआई कोम्युनिटी, 13. सीएम ब्राउसर, 14. वायरस क्लीनर, 15. एपीयूएस ब्राउसर, 16. रॉमावी, 17. क्लब फैक्टरी, 18. न्यूजडॉग, 19. ब्यूटी प्लस, 20. वीचैट, 21. यूसी न्यूज, 22. क्यूक्यू मेल, 23. विबो, 24. एक्सेंडर, 25. क्यूक्यू म्यूजिक, 26. क्यूक्यू न्यूजफीड, 27. बिगो लाईव, 28. सेल्फीसिटी, 29. मेल मास्टर, 30. पैरलल स्पेस, 31. एमआई वीडियो कॉल – जियोमी, 32. वीसाईंक, 33. ईएस फाइल एक्सप्लोरर, 34. वीवा वीडियो–क्यूयू वीडियो इंक, 35. मीटू, 36. विगो वीडियो, 37. न्यू वीडियो स्टेटस, 38. डीयू रिकॉर्डर, 39. वाल्ट–हाईड, 40 केच क्लीनर डीयू एप स्टूडियो, 41. डीयू क्लीनर, 42. डीयू ब्राउसर, 43. हेगो प्ले विथ न्यू फ्रेंडस, 44. कैम स्केनर, 45. क्लीन मास्टर–चीता मोबाइल, 46. वांडर केमरा, 47. फोटो वोंडर, 48. क्यूक्यू प्लेयर, 49. वी मीट, 50. स्वीट सेल्फी, 51. बैडू ट्रांसलेट, 52. वीमेट, 53. क्यूक्यू इंटरनेशनल, 54. क्यूक्यू सिक्यूरिटी सेंटर, 55. क्यूक्यू लॉन्चर, 56. यू वीडियो, 57. वी फ्लाई स्टेटस वीडियो, 58. मोबाइल लीजेंडस, 59. डीयू प्राईवेसी

https://www.jagran.com/delhi/new-delhi-city-ncr-amidst-border-dispute-center-ban-59-chinese-apps-swadeshi-jagran-manch-said-well-done-modi-20453127.html

डिजिटल हस्ताक्षर अभियान से जुड़े तेरह लाख लोग

स्वदेशी जागरण मंच की अपील पर अब तक 13 लाख से अधिक लोग चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार की मुहिम से जुड़े हैं। हर दिन एक लाख लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से चलाए गए डिजिटल हस्ताक्षर अभियान के दौरान यह आंकड़ा सामने आया है। स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक अश्विनी महाजन ने आईएएनएस को बताया, "हस्ताक्षर अभियान की शुरूआत में 20 से 25 हजार लोग जुड़ रहे थे, लेकिन चीन के खिलाफ इधर बीच देश में उठे गुस्से के बीच तेजी से लोग हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। अब हर दिन एक लाख लोग ऑनलाइन अभियान से जुड़े रहे हैं। अभियाान को लेकर लोगों में उत्साह को देखते हुए हस्ताक्षर अभियान अभी चलता रहेगा।"

दरअसल, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी स्वावलंबन अभियान संचालित किया है। इस अभियान के तहत लोग चाइनीज सामानों को न खरीदने का संकल्प लेते हुए संबंधित लिंक पर ऑनलाइन अपना ब्योरा भरते हैं। यह लिंक स्वदेशी जागरण मंच ने तैयार किया है।

स्वदेशी जागरण मंच ने लोगों को स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए कई सुझाव दिए हैं। इसमें लोगों से सिर्फ स्थानीय और स्वदेशी उत्पाद ही खरीदने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लोगों को उद्यमी और स्वरोजगारी बनने

की भी सलाह दी जा रही है। स्वदेशी जागरण मंच, गौ आधारित जैविक खेती पर पर भी जोर दे रहा है। संगठन का मानना है कि इससे किसानों की कमाई बढ़ेगी।

http://www.samacharnama.com/rashtriya-swayamsevak-sangh-campaigned-1-3-million-people-involved-in-boycott-of-chinese-goods/

स्वावलंबी भारत के लिए स्वजाम ने दिए पांच सुझाव

स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी और स्वावलंबी भारत के समर्थन में डिजिटल हस्ताक्षर अभियान को स्वदेशी स्वावलंबन अभियान नाम दिया गया है। संगठन ने समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए कुल पांच सूत्र दिए हैं। स्वदेशी जागरण मंच ने पांच सुझावों में अपील की है कि लोग सिर्फ स्थानीय और स्वदेशी उत्पाद ही खरीदें। बहुत मजबूरी में ही विदशी सामान खरीदें।

संगठन ने लोगों को उद्यमी और स्वरोजगारी बनने की सलाह दी है ताकि दूसरों को रोजगार देने में सफल हों। इससे हर गांव और जिले को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है। तीसरे सुझाव के तौर पर स्वदेशी जागरण मंच ने गौ आधारित जैविक खेती पर बल दिया है और कहा है कि इससे किसानों की कमाई बढ़ेगी। लघु, कुटीर उद्योगों व स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा।

स्वदेशी जागरण मंच ने भारत के हितों के अनुरूप वैश्विक व्यापार, पूंजी व तकनीक के लेनदेन पर जोर देते हुए कहा है कि तभी भारत वैश्विक ताकत बन सकेगा। पांचवे और आखिरी सुझाव के तौर पर लोगों से जल, जंगल और जमीन और जानवरों की रक्षा करने और योग, स्वच्छता को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

स्वदेशी जागरण मंच ने लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील करते हुए कहा है, "सब मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी स्वावलंबन अभियान का हिस्सा बनें, ताकि समृद्ध और स्वावलंबी भारत बनाया जाए।"

http://www.samacharnama.com/swadeshi-jagran-manch-gave-5-tips-for-self-supporting-india/

स्वदेशी कोई नारा नहीं, समाज की सुव्यवस्था का आधार है– भाग्गैया

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाहक श्री भाग्गैया जी ने कहा है कि स्वदेशी कोई नारा नहीं है या अभियान मात्र नहीं है, बल्कि यह समाज की सुख, समृद्धि, सुरक्षा और शांति सहित समग्र व्यवस्थाओं का आधार है। विकास के वर्तमान आर्थिक विकास के मॉडल का अनुसरण करते हुए प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करके मनुष्य के उपयोग के लिए व्यवस्थाएं खड़ी की गई हैं, जिसके कारण विश्व में अशांति, अविश्वास, अराजकता और असंतोष बढ़ता जा रहा

है। इसके कारण विश्व में इस व्यवस्था से यू टर्न लेने की व्याकुलता बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि विकास के इस विनाशकारी मॉडल को बदलने हेतु स्वदेशी जागरण मंच द्वारा, स्वदेशी स्वावलंबन अभियान प्रारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि परिवार के संगठनों के अतिरिक्त गायत्री परिवार, जग्गी जी महाराज सहित कई अन्य संगठनों ने भी इस अभियान को अपना अभियान माना है।

पूज्य सरसंघचालक जी ने भी स्वदेशी का आह्वान किया है। उन्होनें कहा है कि पिछले 250 वर्षों को छोड़ दें तो भारत सदैव ही संपन्न गांवों का देश रहा है। तेलंगाना के गांव का लोहा इंग्लैंड जाता था, बंगाल और तमिलनाडु के गांवों से कपड़ा निर्यात होता था। वर्तमान में भी विजयवाड़ा में गो आधारित संस्था ने रू. 5 करोड़ का लाभदायक उत्पादन किया है। इस अभियान का उद्देश्य यही है कि कृषि को विकास का आधार बनाया जाए और इसका केंद्र ग्राम हो। वर्तमान में आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन के उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकार की नीतियों में यह परिलक्षित भी हो, जो कि इस अभियान का हेतु है।

श्री भाग्गैया जी स्वदेशी जागरण मंच के स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के समन्वयक श्री सतीश कुमार द्वारा लिखित पुस्तक 'भारत मार्चिंग टूवर्ड स्वदेशी एण्ड सेल्फ़ रिलायंस '(अंग्रेजी) 'स्वदेशी स्वावलंबन की ओर भारत' के ऑनलाइन विमोचन के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। स्वदेशी जागरण मंच द्वारा 20 मई, 2020 से स्वदेशी स्वावलंबन अभियान शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के पहले चरण में, डिजिटल हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया था, जिसमें लोग चीनी सामानों के बहिष्कार का संकल्प ले रहे हैं। अब तक 13 लाख से अधिक लोग इस संबंध में शपथ ले चुके हैं और संख्या तेजी से बढ़ रही है।

स्वदेशी स्वावलंबन अभियान का उद्देश्य स्वदेशी और आत्म–निर्भरता के लिए जागृति और प्रतिबद्धता जगाना है। स्वावलंबन को स्वदेशी उद्योग का कायाकल्प करके प्राप्त

किया जा सकता है, जिसमें लघु उद्योग, लघु व्यवसाय, कारीगर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सहित ग्रामीण उद्योग और अन्य गैर–कृषि गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य रोजगार को प्रोत्साहन के साथ समावेशी विकास करना है।

हम देश के लगभग 700 जिलों तक पहुँच चुके है। इस अवधि के दौरान, टीवी चैनल, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों से भी यह पता चलता है कि देश में लगभग हर कोई स्वदेशी का उपयोग करने और चीनी का पूर्ण बहिष्कार करने का संकल्प ले रहा है। चीनी निवेश के लिए सरकारी अनुमति अनिवार्य करके सरकार ने पहले ही चीनी निवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद चीन से आयातों पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, चीनी कंपनियों द्वारा निविदाएं बड़ी संख्या में रद्द की जा रही हैं और कुछ दिनों पहले 59 चीनी ऐप को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

पिछले लगभग डेढ़ महीने में, एक प्रक्रिया शुरू की गई है जिसमें छोटे उद्योगों को फिर से जीवंत करने के उद्देश्य से श्रमिकों, किसानों, छोटे पैमाने के उद्यमियों, शिक्षाविदों, टेक्नोक्रेट और उद्योग और व्यापार जगत के नेताओं सहित सभी क्षेत्रों के लोगों को शामिल किया गया है। विभिन्न संगठनों और संघों के सहयोग से, हम लोगों तक पहुंच बना रहे हैं और उन्हें स्वदेशी/स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और स्वदेशी/स्थानीय उत्पादों की सूची वितरित करके स्वावलंबन के लाभों से अवगत कराया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए उद्योग, व्यापार से जुड़े लोगों को शामिल करते हुए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जा रहा है।

सामान्य रूप से लोग समझने लगे हैं कि यह उन स्थानीय उद्योगों को पुनर्जीवित करने का समय है, जो वैश्वीकरण के युग में हाशिये पर चले गए थे। यह उन आर्थिक नीतियों की शुरुआत करने का भी समय है जो कल्याण, स्थायी आय, रोजगार सृजन में मदद करती हैं और सभी के लोगों में विश्वास पैदा करती हैं।

देश में 700 से अधिक एमएसएमई क्लस्टर हैं। इन समूहों का औद्योगिक विकास का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। चीन से अनुचित प्रतिस्पर्धा और अनुचित आयात नीतियों के कारण इनमें से कई औद्योगिक समूहों को नुकसान हुआ। उन्हें हर तरह से समर्थन और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि वे न केवल रोजगार के अवसर पैदा करें बल्कि सबसे किफायती लागत में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करें। विनिर्माण क्षेत्र में भविष्य में वृद्धि की शुरुआत के लिए पूरे देश में जिला स्तर पर ऐसे औद्योगिक समूहों की पहचान की जा रही है।

भारत में आत्मनिर्भर बनने में ग्रामीण शिल्प और कृषि आधारित उत्पाद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, कृषि आधारित गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में असीमित अवसर उपलब्ध हैं, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, डेयरी, मछली पालन, मशरूम की खेती, बांस की खेती शामिल हैं। फूलों की खेती, बागवानी और अन्य। एकीकृत ग्रामीण विकास समय की जरूरत है। इसके लिए जागरूकता पैदा की जा रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के तहत, स्थानीय, छोटे पैमाने के निर्माताओं, कारीगरों और छोटे व्यवसायों को संभालने का यह समय है। स्वदेशी जागरण मंच ने उद्योग के लिए समस्याओं की पहचान करने के लिए कई क्लस्टर अध्ययन किए हैं। कई मामलों में स्वदेशी जागरण मंच का हस्तक्षेप महत्वपूर्ण साबित हुआ है। इस तरह के अध्ययनों को घरेलू उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए एक मिशन मोड में किया जाएगा।ग्रामीण क्षेत्रों में सफल प्रयोगों को ग्रामीण लोगों के बीच प्रचारित किया जाएगा ताकि वे खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित अन्य गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित हो सकें।

https://www.swadeshnews.in/newdelhi/india-marching-towards-swadeshi-and-self-reliance-book-released-527364

मंच के कार्यकर्त्ताओं ने शी जिनपिंग का पुतला फूंका

स्वदेशी के प्रसार व चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए लोगों को प्रेरित करने के मकसद से स्वदेशी जागरण मंच (अमृतसर) द्वारा जुझार सिंह नगर अजनाला रोड में घर–घर संपर्क अभियान चलाया गया। इसके अलावा मंच के कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला भी फूंका। मंच के महानगर संयोजक एवं स्वदेशी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अरविंदर शर्मा ने कहा कि विदेशी वस्तुओं विशेषकर चीन निर्मित वस्तुओं का बहिष्कार कर ही हम स्वदेशी को अपना सकते हैं। यह शहीदों को भी श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर कमल खन्ना, राहुल कपूर, अशोक ठुकराल, गौरव सहगल, सरवन सिंह व युवा विद्यार्थी आदि उपस्थित थे।

https://www.jagran.com/punjab/amritsar-jagran-manch-starts-swadeshi-camaign-20489453.html

स्वदेशी अपनाना वक्त की मांग–कश्मीरी लाल

चीन से सीमा पर तनातनी के बाद स्वदेशी अपनाने की मुहिम एक बार फिर तेज हो गई है। आत्मनिर्भर अभियान को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्य भूमिका में है। संघ के सहयोगी संगठन भी आम लोगों को जागृत कर रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच तो रसोई, बाथरूम और ड्रेसिंग टेबल को शत प्रतिशत स्वदेशी बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री कश्मीरी लाल ने लोकतंत्र सेनानी संघ की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि स्वदेशी अपनाना वक्त की मांग है।

आज की परिस्थिति में स्वदेशी के आंदोलन को अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। हमें अपनी रसोई, बाथरूम और ड्रेसिंग टेबल इन तीन स्थानों पर शत प्रतिशत स्वदेशी को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में स्वदेशी की उपयोगिता पर आयोजित ऑनलाइन विचार गोष्ठी में लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय मंत्री धर्मवीर शर्मा ने कहा कि संगठन राष्ट्रहित में निरंतर कार्यरत है।

स्वदेशी अपनाने पर जन जागरण अभियान चला रहा है। हर घर की रसोई, बाथरूम और ड्रेसिंग टेबल स्वदेशी सामान के लिए अभियान चलाया जाएगा ताकि विदेशी चीजों पर निर्भरता खत्म हो और हम आत्म निर्भर बनें।

https://www.amarujala.com/delhi-ncr/rss-spreads-awareness-to-promote-indian-goods-rather-than-imported-chinese-materials

चीनी कंपनियों को भारत में टेंडर न भरने दिया जाएः स्वजामं

चीन के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद देश में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इस घटना के बाद देश में एक बार फिर चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस बीच स्वदेशी जागरण मंच ने केन्द्र सरकार से अपील की है कि चीनी कंपनियों को भारत मे टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जाय, चीनी सामानों पर रोक लगाया जाय व किसी भी प्रकार से चीनी सामानों को भारत में आने से रोका जाये।

इसके साथ ही मंच ने लोगों से भी चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अपील की है। स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने बातचीत में कहा है कि वे फिल्म अभिनेता, खिलाड़ियों और सेलिब्रिटीज से भी अपील कर रहे हैं कि चीनी ब्रांड का प्रोमोशन न करें। उन्होंने कहा कि यही शहीद सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही स्वदेशी जागरण मंच ने केन्द्र सरकार से दिल्ली–मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के लिए बोली लगाने वाली चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (एसटीईसी) की बोली रद्द करने की भी मांग की है। साथ ही महाराष्ट्र सरकार से भी चीनी ऑटो कंपनी के साथ हुए समझौते को रद्द करने की अपील की है।

http://www.samaylive.com/nation-news-in-hindi/421008/chinese-companies-should-not-be-allowed-to-file-tenders-in-india-swadeshi-jagran-manch.html

लोगों के बीच स्वदेशी की अलख जगाने में जुटा स्वदेशी जागरण मंच

स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, उसे प्रयोग करने और चीनी वस्तुओं को बहिष्कार करने को प्रेरित करने के लिए देश भर में स्वदेशी एजुकेटर और स्वदेशी वॉलंटियर बनाने का अभियान शुरू किया है। पंजाब, हरियाणा से इसको शुरू किया है, जल्द ही इस देश के अन्य हिस्सों में ले जाया जाएगा।

इसके अलावा स्वदेशी सामान अपनाने से जुड़े अभियान से अभी तक 20 देशों के करीब 6 लाख लोग जुड़ चुके हैं। बताया जाता है कि इसमें अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, जापान और नेपाल जैसे देशों में रहने वाले भारतीय खुद से इस अभियान के संकल्प पत्र को भरकर हस्ताक्षर कर रहे हैं।

स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक अश्विनी महाजन ने बताया कि मंच युवाओं को स्वेदशी एजुकेटर बना रहा है जो स्कूलों और कॉलजों में बच्चों–युवाओं को स्वदेशी चीजें अपनाने के लिए जागरुक कर सकें। हरेक प्रांत से करीब 8–10 युवाओं को इसमें जोड़ा जाएगा।

महाजन ने कहा कि फिलहाल चीन के सामान का बहिष्कार करना और भविष्य में आत्मनिर्भर होकर विदेशी सामान नहीं खरीदने के लिए लोगों को जागरुक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में स्वदेशी एजुकेटर को पंजाब, हरियाणा से शुरू किया है। जल्द ही राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित देश भर में इसको चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान के साथ ज्वाइन स्वदेशी अथवा स्वदेशी वॉलंटियर या वॉरियर के जरिए वॉलंटियर्स की टीम भी तैयार कर रहे है। संगठन ने ये अभियान गूगल के माध्यम

से चलाया है और बड़ी संख्या में लोग फॉर्म भरकर स्वदेशी अपनाने व वॉलंटियर बनने का संकल्प कर रहे हैं। मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुशील पांचाल ने कहा कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेने वालों को स्वदेशी एजुकेटर में शामिल किया जा रहा है।

ये स्कूलों और कॉलेजों में जाकर बच्चों–युवाओं और अलग–अलग मंचों से लोगों से स्वदेशी को अपनाने के लिए बात करेंगे। उन्हें इसके फायदे समझाएंगे। उन्होंने कहा स्वदेशी एजुकेटर के लिए किसी विशेषता की जरूरत नहीं है, कोई भी अपनी स्वेच्छा से बन सकता है।

उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण के मंच के साथ में वीएचपी और उसकी युवां शाखाएं बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता भी घर–घर जाकर लोगों से स्वदेशी वस्तुएं अपनाने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

https://www.navodayatimes.in/news/khabre/cesarean-deliveries-decreased-from-fear-of-coronavirus-infection-prsgnt/150154/

ब्रिटेन में भी लगी हुवावे पर पाबंदी

अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी अपने 5जी टेलीकॉम नेटवर्क से हुवावे को बाहर करने का फैसला ले लिया है। इस फैसले ने जनवरी में दिए हुवावे के बयान को उलट दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि हुवावे को देश के सुपर–फास्ट वायरलेस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की सीमित भूमिका मिल सकती है। ब्रिटेन सरकार ने घोषणा की कि उनके 5जी नेटवर्क से मौजूदा हुवावे इक्विपमेंट्स हटाने के लिए बी.टी. और वोडाफोन जैसे ऑपरेटरों को 2027 तक का समय दिया गया है। डिजिटल और संस्कृति मंत्री ओलिवर डाउडेन ने कहा कि मई में हुवावे पर लगाए गए नए अमेरिकी प्रतिबंधों ने पूरी तस्वीर को बदल दिया है। डॉउडेन ने कहा कि यूके को अब यह विश्वास नहीं है कि भविष्य के हुवावे 5जी इक्विपमेंट्स की सुरक्षा की गारंटी देने में सक्षम होगा।

https://money.bhaskar.com/tech-auto/news/uk-bans-huawei-from-its-5g-network-in-rapid-about-face-the-company-said-this-is-a-political-conspiracy-the-decision-was-taken-not-on-security-but-on-american-trade-policy-127514955.html

हांगकांग के रास्ते आने वाले चीनी माल पर भी बढ़ेगी सख्ती

भारत में हांगकांग के रास्ते आने वाले माल को लेकर सरकार सख्त जांच प्रक्रिया लागू करने की तैयारी कर रही है। ऐसा चीन के साथ बढ़े तनाव के बीच हांगकांग से बीते चार साल में तीन गुना आयात बढ़ने के बाद हुआ है। सरकारी अधिकारियों को अंदेशा है कि चीन से आयात रोकने पर वह अपना माल हांगकांग के जरिये भारत भेज रहा है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि वित्त वर्ष 2019–20 में चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में कमी आई, लेकिन हांगकांग के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि जब भारत घरेलू माल को बढ़ावा देने के लिए चीनी माल के आयात पर सख्ती बढ़ा रही है तो उसे वियतनाम, हांगकांग और बांग्लादेश जैसे देशों से आयातित माल पर सख्त रुख अख्तियार करना होगा। ऐसा नहीं करने से इन देशों से चीनी सामाना को भारत भेजा जाता रहेगा। सूत्रों के अनुसार, भारत का वाणिज्य मंत्रालय को हांगकांग के जरिये सामान भेजने की भनक लग गई है। इसलिए मंत्रालय तुरंत इस दिशा में जांच के लिए सक्रिय हो गया है। अब मंत्रालय हांगकांग के साथ बढ़ते व्यापार घाटे की समीक्षा कर रहा है जिससे हांगकांग रूट से आने वाले चीनी सामान की भी रोकथाम की जा सके।

भारत में हांगकांग के रास्ते बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात होता है। उदाहरण के लिए हांगकांग से तीसरा सबसे अधिक मात्रा में आने वाला सामान डिजिटल सर्किट है जो पहले चीन से आता था। लिथियम आयन बैटरी का आयात भी इसी तरह हांगकांग के रास्ते तेजी से बढ़ा है। मोबाइल में लगने वाला मेमोरी कार्ड के आयात में भी हांगकांग से बड़ा उछाल आया है। विदेश व्यापार विशेषज्ञों के मुताबिक, भारत को हांगकांग के साथ वियतनाम और बांग्लादेश पर भी निगरानी रहने की जरूरत है। वियतनाम का चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) होने की वजह से चीन का सामान वियतनाम में धड़ल्ले से आ सकता है। चीन के कारोबारी इस संधि का फायदा उठाते हुए अपने माल को वियतनाम के रूट से भारत भेज सकते हैं क्योंकि वियतनाम से आने वाले सामान को वियतनाम का माना जाएगा।

कोरोना महामारी ने भारतीय निर्यातकों के सामने भी संकट खड़ा कर दिया है। यूरोपी और अमेरिकी कंपनियां क्रिसमस की खरीदारी पर भारतीय निर्याताकों से 20 से 25 फीसदी की छूट मांग रहे हैं। साथ ही उधारी की अवधि भी बढ़ाने की मांग कर रहे है। मौजूदा समय में उधारी की अवधि 60 दिन है जिसे वो बढ़ाकर 90 दिन करने की मांग कर रहे हैं। कोरोना संकट से भारत के कपड़ा, चमड़े के सामान, हैंडीक्राफ्ट, स्टील, ज्वैलरी, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र पर सबसे बुरा असर पड़ा है। इसमें अलगे चार महीने सुधार होने की संभावना बहुत ही कम है।

https://www.livehindustan.com/business/story-shock-to-china-strictness-will-increase-on-goods-coming-through-hong-kong-3348809.html

चीन और चीनी वस्तुओं के खिलाफ प्रदर्शन

सचित्र झलक

यमुना विहार विभाग, दिल्ली

पलामू, झारखंड

कोटा, राजस्थान

रोहिणी, दिल्ली

बटाला, पंजाब

फरीदाबाद, हरियाणा

अलीगढ़, उत्तर प्रदेश

सिहोर, मध्य प्रदेश

स्वदेशी पत्रिका
डाक तिथि 15—16 जून 2020 नई दिल्ली पी.एस.ओ.
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/1/4074/2018-19-20
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

चीन और चीनी वस्तुओं के खिलाफ प्रदर्शन

सचित्र झलक

ब्रहमपुर, ओडिशा

आर.के.पुरम्, नई दिल्ली

यमुना विहार, दिल्ली

होशियारपुर, पंजाब

जोधपुर, राजस्थान

द्वारका, दिल्ली

परवाणू, हिमाचल प्रदेश

दिल्ली

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती